(Shri Niren Ghosh.]

not help you for ever. As they demonstrated on 17th November, if necessary, time and again the people and the workers of West Bengal will demonstrate their strength.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Code of Civil Procedure (Amendment) BUI, 1973

SECRET ARY-GFNIiRAL: Sir, 1 have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of Rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, 1 am directed to inform you that Lok Sabha at its sitting held on the 19th November, 1973, agreed without any amendment to the Code of Civil Procedure (Amendment) Rill, 1973, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 12th November, 1973."

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Hoiisg stands adjourned till 2 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock.
Mr. Deputy Chairman in the Chair

REFERENCE TO ALLEGED ATTACK ON THE NEW AGE PRESS

SHRI LAL K. ADVANI (Delhi) : Sir, on a point of personal explanation. Just before we broke for lunch, Shri Bhupesh Gupta made a statement, referring to me personally and saying that the Ian Sangh people had attacked the New Age Press. I was in fact taken completely by surprise, although on the spot I said it cannot be true. I went and made enquiries and what I found was that perhaps their Delhi paper, Hindi paper, wrote something about the Shyam Lai College—there is a Shyam Lai College in Shahdara—and against the students of that college. It is this that led to this incident. I only want to point out that the Ian Sangh has nothing to do with this happening. The Editor of the Motherland—whose office happens to be close by—his car has also been damaged in the stone throwing and all that.

Therefore, Sir, I would appeal Ihrough you to the entire House that when allegations of this kind are made against political parties as a whole they should be done with the utmost sense of responsibility and such sweeping statements should not be made.

MOTION RE TWENTIETH REPORT OI THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1970-71—Contd.

श्री एन० पी० चौधरी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, हमारे सामने शिड्यूल्डकास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स आयुक्त द्वारा बीसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत है जिस पर हम विचार कर रहे है। जब सदन में शिड्यूल्डकास्ट और शिड्ल्ड ट्राइब्स का कोई मामला आता है तो हम लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है और हम लोग देखते है कि आखिर हम लोगों कि जो पिछली स्थिति थी उससे आज हम कहां तक आगे बढ़े है। जब हम विस्तार पूर्वक इस रिपोर्ट को देखते हैं या उन बातों को देखते हैं, तो दुःख होता है कि जितनी प्रगति हमने पिछले बार की थी उससे अगले साल ज्यादा प्रगति नहीं की है बल्कि हम वहीं के वहीं पर ही रह जाते है।

आपको याद होगा कि जब भारतवर्ष आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय हरिजन और आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब थी। हमारे देश में जो नेता था उनके हृदयों में उनके प्रति बहुत ही अच्छी सहानुभूति थी। बापू के बारे में

आप जानते है कि उनका एक स्वपना था और वह लोगों से कहा करते थे कि मैं उस दिन संसार में सब से सुखी आदमी हूंगा जिस दिन मैं यह देखूंगा कि हमारे देश का प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति एक हरिजन व्यक्ति बनाया जाता है। इस तरह की कल्पना बापू की थी। उसके बाद हमारा राष्ट्र आजाद हुआ और आजादी के बाद उनके उत्थान के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और उनकी प्रगति के लिए अनेक प्रावधान संविधान में किये हैं। मैं विशेषकर यह बात कहना चाहता हूं कि हमने जो लक्ष्य पूर्ति के लिए रखा था उससे बहुत कम प्रगति इस दिशा में की है। मेरा यह ख्याल है कि जो बीसवीं रिपोर्ट सदन के समक्ष है, उसमें इस बारे में पूरा लेखाजोखा दिया हुआ है और आप इसमें देखेंगे कि इन लोगों के लिए कोई विशेष राहत दिखलाई नहीं देती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी सदन में हरिजनों या आदि-वासियों के अत्याचार, मारपीट या उत्थान की बात आती है तो हमारे नेताओं की ओर से हमेशा आश्वासन मिलते रहते हैं कि हरिजनों और आदि-वासियों की उन्नति तथा प्रगति के लिए सरकार की ओर से सब तरह का प्रोत्साहन दिया जायेगा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हम वहीं के वहीं पर हैं।

मुझे एक कहावत याद आ जाती है और वह इस प्रकार से है:

"तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौना देकर बहलाया गया हूं"

तो इस तरह से जब कभी भी हरिजनों के उत्थान की बात आती है तो हमारे हाथ में कोई खिलौना दे दिया जाता है आश्वासन के रूप में और थोड़ी देर के लिए हम चुप हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्थिति देखते हैं तो अपने को वहीं पर पाते हैं। वही स्थिति आज भी हम देखते हैं। यह बात मैं आप से इसलिए कह रहा हूं कि जो आयुक्त की रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें यह प्रमुख बात उठाई गई है कि हमने कहां तक प्रगति की है और इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत कम काम हुआ है। हमारे कमिश्नर महोदय यहां तक कहते हैं कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रगति नहीं हुई है और इम्प्लीमेंटेशन में गति नहीं लाई गई है। अगर इस इम्प्लीमेंटेशन में तेजी नहीं लाई गई तो यह समस्या इतनी भयंकर हो जायेगी कि उसको सम्भालना बहुत मुश्किल हो जायेगा। तो इस चीज से आप को समझ लेना चाहिये कि हम कहां पर हैं और कैसी स्थिति पर हैं। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार सदन में जब यह मामला लाया गया था और जो आश्वासन दिये गये थे तथा संविधान में इन लोगों को जो अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में आपने कहां तक प्रगति की है? सचमुच जब हम कोई समस्या सदन के सामने लाते हैं, कोई बात लाते हैं, तो हम से कह दिया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पास फंडस नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो हम कहां से पैसा लायें? क्या आप यह चाहते हैं कि उनका उत्थान न हो और जैसी स्थिति में वे लोग हैं वैसी स्थिति में वे लोग बने रहें। इस तरह का जो बहाना है वह अच्छा नहीं है। इस चीज के लिए विचार करना होगा कि पंचवर्षीय योजना में देश की प्रगति के लिए जो रुपया लिया जाता है उसमें हरिजन और आदिवासियों की भलाई के लिए कितना खर्च किया जायेगा। आप को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि हरिजनों और आदि-वासियों की आबादी देश की आबादी का 35 प्रतिशत है। आप पंचवर्षीय योजना में देश की उन्नति के लिए जितना रुपया रखते हैं उसी हिसाब से हरिजन और आदिवासियों की जो आबादी है उनके लिए भी उसी प्रतिशत से अलग से रुपया रखा जाना चाहिए। मैं कोई कारण नहीं देखता कि उसमें किसी प्रकार की कमी की जाय। यदि आप कमी करते हैं तो मैं ऐसा सोचूंगा कि आप हमारे प्रति न्याय

[श्री एन॰ पी॰ चौधरी]

नहीं कर रहे हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है। जितनी हमारी आबादी है, जितना हमारा प्रतिशत है, जितनी हमारी समस्याएं हैं उसको देखते हुए पैसा पंचवर्षीय योजनाओं में हमें देना चाहिए।

स्कालरशिप की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्कालरशिप्स की तरफ आप देखें तो आपको यह मालूम होगा कि जो आज से 20 साल पहले रेट निर्धारित किए गए थे, जो दरें निर्धारित की गई थीं करीब वही दरें आज भी चल रही हैं। मंहगाई कहां से कहां पहुंच गई है। 300 प्रतिशत के करीब महंगाई इन बीस सालों के अन्दर बढ़ गई है परन्तु स्कालरशिप की दरें वही हैं। बार-बार हमने यहां मांग की है। अनेक सदस्यों ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि कम से कम बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए आप स्कालरशिप के लिए कुछ प्रावधान बढ़ाएं. कुछ और अधिक पैसा दें जिससे ये साधनहीन और गरीब व्यक्ति ठीक से शिक्षा प्राप्त कर सकें, परन्तु दुःख है कि इस दिशा में भी अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। यदि शासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो मुझे यह कहते दुख होता है कि वह समय आएगा जबकि धीरेधीरे ये हरिजन और आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़े रह जाएंगे और अशिक्षित बने रहेंगे।

शहरों में या गांवों में उनके रहने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं पर छात्रावासों का प्रावधान है, परन्तु अनेक जगहों में छात्रावासों का प्रबन्ध न होने के कारण दूर दूर से आने वाले हरिजन और आदिवासी छात्रों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे हृदय से यह चाहते हैं कि हरिजन और आदिवासी लोगों में शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षा का लाभ उन्हें मिले तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हर जिले में और हर तहसील में छात्रावास का प्रबन्ध हो और उसके लिए आपको प्रावधान करना पड़ेगा। जब इस तरह का प्रावधान हो जायगा तब शिक्षा की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, और उस दिशा में प्रगति हो सकेगी। विशेषकर मैं हरिजन और आदिवासी छात्राओं की ओर लड़कियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जब लड़कों में शिक्षा का इतना प्रसार नहीं है तो लड़कियों के बारे में तो हम कल्पना कर सकते हैं। उनको बहुत कम शिक्षा प्राप्त है। तो उनको इस ओर आकर्षित करने के लिए हमें और भी आकर्षक योजनाएं लानी पड़ेंगी. उनकी सुरक्षा की, उनके रहने की, खाने-पीने की और स्कालरशिप की बातों में हमें सुधार करना पड़ेगा और उसके लिए अधिक प्रावधान करना पड़ेगा जिससे कि वे इस दिशा में आगे बढ़ सकें।

जहां तक रोजगार की समस्या है, आप जानते हैं कि हमारे लिए हरिजन और आदिवासियों के लिए 15 परसेंट और साढ़े 7 परसेंट का रिजर्वेशन तो है, लेकिन मैं यह देखता हूं कि वह कोटा अनेक वर्षों से पूरा नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जहां हमारा 15 परसेंट रिजर्वेशन है वहां मुश्किल से दो चार परसेंट मिला हुआ है। यह हालत है। जब हम यहां पर प्रश्न करते हैं कि हमारा यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारे रिजर्वेशन के अनुसार, हमारे परसेंटेज के अनुपात में जगह क्यों नहीं दी जा रही है तो बहाना यह बनाया जाता है कि हमें उचित कंडीडेट नहीं मिलते। यह एक कोरा बहाना है, बिना आधार का बहाना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हर क्षेत्र में शिक्षित हरिजन और आदिवासी छात्र उपलब्ध हैं। अगर वे दूसरे छात्रों की तुलना में अच्छे हैं तो उनका अधिकार क्यों नहीं दिया जाता, यह बहाना करके उन्हें क्यों टाला जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो इस दिशा में सिफारिश की गई हैं, हमारे कमिश्नर ने जो निवेदन किया है उसे आपको देखना पड़ेगा और जो रिजर्वेशन में गैप बढ़ता जा रहा उस गैप को पूरा करने के लिए आपको

परसेंटेज में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि इस गप को पूरा करने के लिए आपको कहीं कहीं पर मास स्केल पर हरिजन और आदिवासियों का रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, उनकी भरती करनी पड़ेगी जिससे उनको उनका अधिकार मिल सके और यह गैप भी पूरा हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में उनको बहुत कम काम मिलता है। जब सीजन आता है तब थोड़ा बहुत काम मिल जाता है। उसके बाद उनको कोई काम नहीं रहता, भूखे भटकते फिरते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब उन्हें काम न हो तो सरकार की ओर से काम मिले। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे कि वे अपनी रोजी-रोटी चला सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूरी मिलती है उससे भी आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आपको मालूम है कि बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम वेजेज का प्रोत्साहन होना चाहिए, मीनिमम वेज प्रैस्क्राइब होनी चाहिए जिससे कि वहां के मजदूरों को कम से कम रोजी और रोटी का सहारा मिल सके। दो टाइम पेट भर भोजन मिल सके इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आपको शायद मालूम होगा कि महाराष्ट्र शासन ने इस दिशा में एक कदम उठाया है और उसका लोगों ने काफी अच्छा स्वागत किया है।

जहां तक दफ्तरों में नौकरियों का, प्रमोशंस का सवाल है उसके बारे में मैं आप से कहना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी हेड आफ दि डिपार्टमेंट के ऊपर होनी चाहिए, उसकी यह ड्यूटी रखनी चाहिए कि वह यह देखें जैसे कि वह कार्यालय का अन्य कार्य देखता है। उसके ऊपर यह जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि वह देखे कि प्रमोशन में, रेक्रूटमेंट में और इसी तरह से दूसरे मामलों में हरिजनों और आदिवासियों को निश्चित प्रतिशत के अनुसार उनके अधिकार मिलें। यदि किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी होती है तो हेड आफ दि डिपार्टमेंट के ऊपर उसकी जिम्मेदारी थोपनी चाहिए उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। जब तक इस दिशा में किसी प्रकार का डेटरेंट पनिशमेंट नहीं होगा, कोई कड़ी सजा की व्यवस्था नहीं होगी और किसी तरह की सजा नहीं होगी तब तक हमारा ऐसा ख्याल है कि जो बड़े बड़े लोग कुर्सी पर बैठे हैं वह हमारे अधिकार हमें नहीं दे पायेंगे और इस तरह से हम भटकते रह जायेंगे।

उपसभापति महोदय, जहां तक आर्थिक उन्नति का सवाल आप जानते हैं कि शिक्षा और नौकरियों के बल पर इनका आर्थिक उत्थान कभी नहीं हो सकता। आर्थिक उन्नति करने के लिए यह जरूरी होता है कि हम रोजगार में, बिजनेस में, उद्योग धंधों और दूसरे मामलों में इनको आकर्षित करें। हम इस दिशा में उनको आकर्षित नहीं करेंगे तो परिणाम यह होगा कि जो सवर्ण लोग हैं वह इस दिशा में प्रगति करते जायेंगे और हरिजन और आदिवासी केवल नौकरियों फंसे रह जाएंगे। इस तरह जो अन्तर आर्थिक क्षेत्र में आयेगा उसको हम पूरी तरह से कम नहीं कर पायेंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को देखें कि चाहे लाइसेंस का मामला हो, चाहे कोटा हो, छोटे छोटे रोजगार धंधे हों उनके लिए अलग से पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए, एक निश्चित दर उनके लिए तय कर दी जानी चाहिए कि प्रति-वर्ष हरिजन और आदिवासियों को इतना पैसा मिलेगा जिससे कि उसका लाभ उठाकर वे अपना आर्थिक उत्थान कर सकें।

जहां तक मकानों का सवाल है, आप जानते हैं कि जो मकान बनाने के लिए उनको पैसा मिलता है वह इतना कम है कि उससे कुत्तों या ढोरों के रहने के लिए भी आज मकान नहीं बनाये जा सकते। जब इतनी कम कीमत में ढोरों और कुत्तों के रहने के लिए भी मकान नहीं बन सकते हैं तो आप कैसे सोचते हैं कि हरिजन

और आदिवासियों के रहने के लिए इतनी कीमत में मकान बन सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस दिशा में विचार करें और अधिक से अधिक पैसा दें जिससे कम से कम उनके रहने के लिए मकान की व्यवस्था हो सके।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात आप जानते हैं। हमारे यहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, मगर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लाभ हमारे हरिजनों और आदिवासियों को कोई नहीं मिला। अगर उसका डाटा इक्कठा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि शायद एक परसेंट भी उसका लाभ नहीं मिल पाया। विभिन्न जातियों के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए आपको देखना होगा और उनके लिए एक परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा कि इतना परसेंटेज उनको प्रतिवर्ष मिलेगा जिससे वह आर्थिक दिशा में उन्नति कर सकें।

आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने आदिवासियों की उन्न त के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाये हैं। मुझे अवसर मिला कुछ ट्राइबल ब्लॉक्स में जाने का। मैं वहां गया तो मैंने वहां निकम्मे अफसर देखे और मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने वहां के कलक्टर के पास और दूसरे अधिकारियों से ा क इतने निकम्मे अधिकारियों को क्यों लाया गया तो उन्होंने ा कि ट्राइबल ब्लॉक्स में ऐसे ही अधिकारी रखे े हैं जो निकम्मे होते हैं, जिनको पनिशमेंट के रूप में देहातों में सरकार भेजना चाहती है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कभी शहरों में भी काम नहीं किया जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया वह गरीब लोगों का क्या भला कर सकेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में ट्रांसफर करने से पहले आप यह देखें कि जो सिंसियर लोग हों, जो लगनशील लोग हों उन्हीं को वहां भेजा जाए जिससे वह इन क्षेत्रों की उन्नति कर सकें।

अत्याचार और अन्याय से आप अनभिज्ञ नहीं हैं। रोज हमें समाचारपत्रों में पढ़ने को मिलता है, मारपीट, लूटपाट, हत्याकांड के समाचार हमारे यहां आते हैं। शासन ने भी हमें अनेकों बार इस के लिए आश्वासन दिया है परन्तु इस में कोई विशेष कमी नहीं आ रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरफ भी ध्यान दें। महाराष्ट्र की एक घटना आप को मालूम होगी। महाराष्ट्र में एक हरिजन की हत्या कर दी गयी परन्तु उस मामले को सुसाइड बना कर दबा दिया गया। मगर जब हमारे कमिश्नर साहब वहां गये तो उन्होंने इसकी जांच की। उस के बाद उन्होंने उस की रिपोर्ट की और उस के बाद ही उस को हत्या का मामला करके दर्ज किया गया। तो इस प्रकार से...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I will call the next speaker now. Shri Goray.

श्री एन० पी० चौधरी : इसी प्रकार बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति जैसे हाईकोर्ट के जजेज हैं या यू० पी० एस० सी० के चेयरमैन का पद है, या पी० एस० सी० के चेयरमैन हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेज के पद हैं उनके लिए आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन पदों के लिए भी हमारे अधिकारों का संरक्षण करें और हम को हमारे अधिकार दिलायें। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं इस के अलावा उन के डाइरेक्टर्स या जो दूसरे फाइनेंशियल कारपोरेशन्स हैं उन में ऊंचे पदों पर हरिजनों और आदिवासियों को लाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि मुझे समय पूरा नहीं मिल सका जिस से मैं अपने पूरे विचार व्यक्त कर सकता लेकिन उस के बाद भी मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए इतना अवसर प्रदान किया।

SHRI N. 6. GORAY (Maharashtra) : Mr. Deputy Chairman, Sir, one cannot escape a sense of disappointment and frustration and even anger when one goes through this Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

for the year 1970-71. It seems that we are not at all serious so far as this problem of the Harijans and the Girijans is concerned. Discussion of this Report in \ this House has become an annual ritual. When it comes to expressing our opinions, we express our sympathy, deep sympathy, and once we leave this House, we just forget everything about it. Sir, you can imagine that this is the 20th Report that we are discussing. And even in this 20th Report, the Commissioner has remarked, almost by way of lament, that there is hardly a single village in the entire country where untouchability is not practised. Ard this year, in spite of the reports to the contrary by the various State Governments, it really raises a question as to how far the Reports can be relied upon, because, Sir, at page 64 of this Report, the Commissioner has pointed out that in realiiy there may be hardly any village in the country which may be termed as absolutely free from this evil. It says : "The survey conducted by our office in Mysore has revealed the existence of untouchability ir. villages that had received prizes for doing excellent work in the removal of untouchability". Sir, this will give you a measure of hypocrisy which is in practice so far as removal of untouchability is concerned. The lethargy with which we are working on this particular subject can be proved by going through the voluminous statement of action taken on the recommendations of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in his Annual Report for 1970-71. There are nearly 151 recommendations. Shri Mirdha is not here but I would like to ask the Deputy Minister who is sitting here jusl now to point out to me a single recommendation that has been implemented ir the spirit in which it was made. Every where, you will find a note by the Gov ernment in explanation that 'this ha been referred to the State concerned' 'action is likely to be taken', 'it is unde consideration' and so on. This yoi will notice on page after page. And eve in respect of the weighty report which wa submitted by the Commission which wa appointed in 1965 under Shri Eliyaperumal, the recommendations of that commission are still under consideration. In order to make stringent laws regarding untouchability a Joint Select Committee has been appointed and even now, i.e. nine years after the appointment of the Commission, the report of the Joint Select Committee is still awaited. This shows the urgency with which we are looking at the problem. We ought to be honest to ourselves. In this House you must have noticed that only today we were so much agitated about the strike staged by the Indian Airlines employees. Every five or six months a handful of people are holding the entire country to ransom and I won't be surprised if they get away with it. Most probably they will get away with it even though the Minister is putting up a brave face. He will climb down and meet their demands. But. what is happening to these lakhs and crores of Harijans and Girijans0 Hardly any notice is being taken. Yesterday we had a debate in which so many hon. Members participated. Today in the press you will not find a single word about it not even a single line about this debate. What has the press come to ? It is only these flashy things, strikes, lock-outs, murders, etc. which attract their attention. Here you see nearly ten crores of people languishing being considered as untouchables. They are not entitled to the rights which a human being should enjoy and this is going on for thousands of years. And, when this House discusses and debates this issue, the press does not think it worthwhile even to publish a single line about it.

Sir. this I mention because whatever ' the discussions that take place here, whatever the resolutions and whatever the promises, the fact remains that because these untouchables and these tribals i have not now a leader of the standing j of Dr. Ambedkar, who could really organise them, give a fight to us and throw a challenge to all of us, this com-

munity remains neglected. Moreover, the very simple recommendations that are made in Report after Report remain unfulfilled. This is a fact of life and 1 would, therefore, request the Minister who is in charge of this subject that this particular question should not be considered as something that can be slurred over or that can wait or that can be postponed for years together. This is not going to happen. I would like the Ministry to take note of the fact that a new generation young people are coming up. In Maharashtra they have organised themselves into whaj they call the Black Panther Movement. I know that it is an imitation of the Black Panther Movement of America. But I can very well imagine that this Black Panther Movement in India will become much more viruleni than the Black Panther Movement ir America because the Harijans and Giri-jans here are treated worse than Negroes in America:* They have a real grievance Therefore, if you do not want violence tc erupt all over, if you do not want this particular community to feel alienated from the main-stream of our national life, then sooner you wake up the better.

Sir, I can give instances after instances from the statement because I think thai far more important than this Report is the statement of what the Governmenl has done. I would only quote to you, Sir, some of these replies that were given by the Government in their statement Nos. 7, 12, 94, 130, 131, 133, 139 and 143. Everywhere you will find procrastination; everywhere you will find delay; everywhere you will find some excuse or the other. But never has this question been squarely faced and the points raised tackled properly whether it is a question of housing or something else.

Just now my friend has made a point about housing. What is the Government's proposal? That 5 per cent is enough just now. And even these 5 per cent of houses are not properly allotted. Why is that happening ? Because still these people are not properly organised. I realy wish Sir, that in some villages and cities in India something like a Naxalite movement starts I amongst these people. Unless that is done we will not wake up. I am not encouraging ; it but you are making it inevitable. What I 1 am pointing out is that. I do not want | to encourage violence, but what is this? If you do not allow people any housing, if you do not look after their medical treatment, if you do not give them any opportunity in the services what will they do?

Take, for instance, the Mahar Regiment. It is only Mahar in name. I pointed it out to the Defence Minister, Shri Jagjivan Ram and asked him 'How many officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are there in the Army?" He said that it will be very difficult to point out. Why? Because in the ranks there are Mahars. And Mahars have a glorious tradition, Sir. Coming from Maharashtra, 1 know that it was the British officers belonging to the East India Company who organised the Mahars and led them against the Marathas, and the last battle between the British and the Marathas was fought 18 miles from Poona where the Mahar Regiment defeated the Marathas. That was in 1818 and the Mahars are keeping that glorious tradition. They are good fighters, militant people— but no officer. How is it? The same excuse. You so to any establishment, go to the nationalised banks, go to the railways, go to the other establishments. Where are they? Nowhere. We sing praises to the late Dr. Ambedkar that he was one of the most brilliant people that India created. Was it a flash in the pan? Does it mean that only one single Ambedkar will emerge out of this community? Given the proper chance there will be any number of them who can rnme up and contribute their best to the development of this country. But they are not given a chance.

Sir, I happen to be a member of the Governing Body of the ICAR, and in the very nrst meeting that I had attended, I

found that there was a demand for de-reservation of posts. How many? Nearly 30. Everywhere it is so. I would like the Minister to go into this. How does it happen that everywhere you reserve a certain percentage in the services for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and after one year, two years or three years these clever officers manage in such a way that there is no eligible candidate available?

AN HON. MEMBER : It is a shame really.

SHRI N. G. GORAY: And then they come forward and say, these posts cannot be filled because no eligible candidate is available and, therefore, we should de-reserve. This is a game that is going on. Evem for those 5 per cent or 7 per cent vacancies which ought to have been filled by these people they say "No eligible candidate is available". This is happening everywhere. Therefore, I would sav that when we discuss these things it is no use only mouthing sjme slogans or indulging in certain good wishes and sympathies and all that. What is the implementation ? That is the main question. And unless that implementation is there you will never be able to satisfy these people.

The young people who are coming up, they understand that (hey will be treated like this—they go to the schools, thanks to your policy. You are giving certain stipends, certain encouragement and certain scholarships to those people. There is a lot of improvement in that. Now nearly two lakhs of them are getting it.

But that means that every year you are creating two lakhs of people who are dis-contended. who are aware of their position in society. They see the difference between that what is constitutionally given to them and what they are getting in practice. I do not want to labour on this point. I would like to see the hands of this Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes strengthened. He is a person who has no hands, no feet; he has to depend entirely on the police machinery there or the administrative apparatus of the various States and that apparatus does not co-operate with him. Just now we cited the instance of one young man in Maharashtra who was slaughtered. The villagers thought that because of him cer tain disease came to the village and he was slaughtered. And what was done afterwards? The prominent people in that village as well as the doctor gave a certificate that this was a case of suicide or something like that. Not until the Commissioner went to the place the truth came out. This will happen. The same is the case of women in Madhuban. In Madhuban in broad daylight the Hari-jan women were brought out, praded through the streets, stripped and then branded with hot irons. And the entire village was watching . . .

AN HON. MEMBER: Real shame.

SHRI N. G. GORAY: ... as if it was some fun. Sir, we have read about people being burnt at the stakes in the Middle Ages but we ha\fc not to go to the Middle Ages at all. This is happening right under our noses. This is what is happening in Maharashtra; this is what is happening in Tamil Nadu; this is what is happening in Bihar. Do you thin"\ that we are in the 26th year of independence? You may think so but do these Scheduled Tribes feel like that? Do these Scheduled Castes feel like that? Do they feel that they are living in independent India, in democratic India where everybody is equal to everybody else ? It is not so. I can give you a number of instances and as I said I can really challenge the Government to show in what way they have taken definite, emphatic steps to implement the various recommendations made by this Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Otherwise we are only just putting up a sort of ploy. You want a Commisioner? All right; you have a Commissioner. But what can the poor Commissioner do? I found that this Commissioner and his wife go to the spot

[Shri N. G. Goray.] whenever they hear of some atrocities make investigations and make a report ant! that is the end of it. You have even dismantled ihe Regional Offices that he had and in the place of those Regional Office now you have zonal offices, one zonal office looking after a bunch of two or three Stales. This is a very highly unsatisfactory condition. Therefore I would beg of you to make this Commissioner into a real source of authority. You must make the law stringent. Here in this Report 1 have come across statements that for the last so many years there is no report from such and such a State. They do not care even to send a report. You have said that so far as co-operatives are concerned theii co-Opcratives should be encouraged. I tell you. Sir. it is a question of training and certain directions have been given that they should be trained but where are the training facilities? In Madhya Pradesh the entry is that the concerned Government has been informed. That is all. Sir, this is going on year after year and there is no improvement anywhere at alt. And that is why there is such a tremendous lot of discontent among the people. These people feel that all this democracy is for the higher castes: it is the game that they are playing at our cost. Therefore 1 would most earnestly request you to go deep into it. Let there be a Commissionner who is really committed to this. I am glad to note that this Commissioner is taking some deep interest in matters concerning these unfortunate people but this is not enough. You must try to rope in as many non-governmental agencies as possible. Do you try to do that? Sir, in my State of Maharashtra one of my comrades, Dr. AdhaV, is going f/om village to village; it is a one-man mission and he is trying to have one well for the entire community. He has not succeeded; there is so much of resistance among the people. Many people think that Maharashtra is an advanced State; it is not.

It is in the same condition as any other State. Only we do things in a better manner. We do not shout about it. We do not brand people in this wa; but the same opposition, the same resistance to this idea of equality is there. You will be surprised that last year Maharashtra was suffering from acute scarcity and crores of rupees were given by the Central Government to dig wells. Now. do you think that these wells which were dlug at the expense of the Central Government are thrown open to all the people? No They says: All right. Have a separate well for the Harijans and ethers and a separate vsell for those who are touchables. Even in scarcity they will not recognise this fact that all of them are sufTereing and there must be a sort of homogeniety. It is not there. Why is it that these things are happing? My simple explanation is that unfortunately we have become so much addicted to politics that we have no time for Social reforms. There was a time when political movement and social reforms used to go hand in hand. Gandhiji always coupled these awo things together. The tradition of the Congress was to have a Congress session one day and the next day have a social reforms session. That tradition is lost. We want to use these communities simply as our agencies for getting more power. Why is it not possible for you to see to it that the Panchayats at the grass-roots work for them? After all these Harijans and Girijans live in the villages. What are the Panchayats doing? What are the Zila Parishads doing? Cannot the State Government say, unless you do this the finances that are put at your disposal will be cut off? You must do this. You will be surprised to know that when Dr. Rao was the Minister for Electricity he accepted this fact that even in electrification the electrician will see to it that the Mahar area is excluded. The entire village is electrified, but not the Mahar area or the Harijan area. They just bypass it. This is what is happening. You must ask people like me who are Members of Parliament, either in Rajya Sabha or Lok Sabha, what we have done in a single year to see that this sort of national integration takes place. Is it not our responsibility, Sir? Is it only that when we come here , and talk on this Report, we show onr

sympathies. We shed tears and then when we go back we forget about it.

SHRI N. P. CHAUDHARI : Crocodile tears.

SHRI N. G. GORAY : It is quite correct. We are very goodi at this. We are very good crocodiles. What 1 am saying is that every Member of Parliament, every member of a Zila Parishad, irrespective of parties, should do something. Is there a party which will say that it is against the removal of untouchability or the upliftment of Adivasis? Everybody will say that he is for it. Then, why is it that we have not been able to deliver the goods? That is because we are not committed. It was not for nothing that in China Mao had to bring about a complete social revolution. He might have done it through violence. Can we not do it voluntarily? If you are not going to do it voluntarily, violence will erupt, because people are not going to take things lying down. Before that happens, let all of us think that we are committed. Whatever our political differences may be, whatever may be the differences in our economic theories, on this single issue 1 think the entire House stands as one. And if that is so, this question should be really solved far ahead of the target date. What is the target dale ? The target date is receding. We are saying that something concrete will be done within the next five years or within the next ten years and nothing is happening. And, therefore, I would beg of you to see to it that this question is not only academically discussed but is implemented in practice. That is the only thing that needs be done about it

श्री रोशन लाल (हिमाचल प्रदेश) : मिस्टर डिप्टी चेयरमैन साहब, शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की बीसवी रिपोर्ट पर, जो इस एवान के जेरे बहस है और बहस चल रही है। मेरे मोहतरिम दोस्त मिस्टर गोरे ने अभी एक नकशा पेश किया, उन्होंने इस किस्म का खाका पैश किया कि न मालूम कितना जुल्म और अत्याचार हो रहा है। इस चीज से मैं इन्कार नहीं करता, लेकिन अगर मैं उनकी हर बात से इत्तिफाक करूं कि पिछले 25-26 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो मेरे लिए यह कहना गैर-मुनासिब होगा। हमारे मोहतरिम मिनिस्टर मिर्धा साहब ने जब यह रिपोर्ट हाउस के सामने रखी तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक साइड की पिक्चर पेश की। रिपोर्ट उसके बिलकुल मुख्तलिफ है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पहलू ब्राइट होता है और एक पहलू डार्क होता है। उन्होंने सिर्फ ब्राइट पहलू रखा, जो गवर्नमेंन्ट करती रही या करना चाहती रही, उस तरफ उन्होंने रोशनी डाली। जो शड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन की है और जो कमियां पाई गई हैं उनकी तरफ उन्होंने कोई इशारा नहीं किया कि ये कम्यूनिटीज जिनके लिए हम हर साल आंसू बहाते हैं या जिनके लिए बहुत कुछ कहते हैं, उन हालात में उन पर क्या गुजरती है ? यह कोई जजबाती बात नहीं है। इसे बड़ी गहरायी से देखने की जरूरत है कि इसके वजूहात क्या हैं ? शेड्यूल्ड कास्ट वा शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की 19वीं रिपोर्ट की जो जनरल रिव्यू है उसमें आपने पहले पैरे में लिख दिया था। हिन्दुस्तान की जो रूरल पापुलेशन है और खास कर एग्रिकल्चरिस्ट, मैं बिना ताज्जुब के यह बात कहना चाहता हूं कि वह न तो गवर्नमेंट के किसी मैयार में यकीन रखती है न कांस्टीट्यूशन मीजर में यकीन रखता है। इतनी दफा जितने हमने कानून या अमेंडमेंट हरिजन या शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सलाह बहबूदा के लिए स्टेट्स के तौर पर या सेंटर के तौर पर लायें हैं या किये हैं उनके मुताबिक काम क्यों नहीं हुए ? ये बुराइयां क्यों पैदा होती रहीं ? इनकी बुनियाद क्या है ? इसकी बुनियाद यह है कि हमारी जो रूरल पापूलेशन हैं उनसे हमें प्यार है। लेकिन वह हमारी जितनी भी पालिसियां हैं, या इनके अलावा कुछ दूसरी पालिसियां हैं, वह उन पर यकीन नहीं रखती। यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कि अनटचेबिलिटी का भी जिक्र आया, एट्रोसिटी का भी जिक्र आया और ये सब चीजें रिपोर्ट में आई। ये चीजें इसमें इसलिए दी जा रही हैं कि हमारे पास जो ज्यादा ताकतवर कम्युनिटी है, जो सर्विसेज को भी डामिनेट करती हैं आप उससे जस्टिस लेना चाहते हैं। यह बिलकुल हकीकत है वह आपको जस्टिस नहीं देगी

[श्री रोशन लाल]

हमारे मिर्धा साहब ने जब अपने ख्यालात का इज़हार किया इस हाउस में तो उन्होंने कहा था कि आज तक आपके तीन लाख बच्चे कालेजेज में जाने लगे हैं। मैं उनका खैर-मकदम करता हूं कि वह यह ख्वाहिश करते हैं कि कुछ बच्चे आला-तालीम के लिए जायेंगे। आपने फरमाया कि हमने ड्योढ़ी फीस कर दी है, 27 के बदले ड्योढ़ी कर दी, साढ़े चालीस कर दी। इस हालत में जिससे देश गुजर रहा है, जितनी महंगाई है, क्या कोई बच्चा प्री-मैट्रिक या मट्रिक इतने रुपये में अपना गुजारा कर सकता है या किसी और का बच्चा कर सकता है? आप थोड़ा बता दीजिए कि कैसे उसका गुजारा होगा?

मुझे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूड ट्राइब्स की एक कमेटी में काम करने का इत्तिफाक हुआ। मैंने बहुत सारी अंडरटेकिंग्स देखीं, वहां जाने का इत्तिफाक हुआ। वहां देखा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के जो नौजवान बच्चे एजुकेशन के लिए जाते हैं या सविसेज के लिए जाते हैं उनको किस लिए नहीं लिया जाता, कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर उनको नहीं लिया जाता? आपने एक रोस्टर मुकर्रर किया हुआ है। आपके सर्कुलर जाते हैं हैड आफ दि डिपार्टमेंट्स को कि इनका जितना रिजर्वेशन का कोटा है उसके मुताबिक उनको दिया जाय। क्या कारण है कि वहां शार्ट-फाल है? वह क्यों नहीं पूरा होता उसका क्या कारण है? मैंने पहले भी कहा था—मैंने किसी कम्युनिटी पर हमला नहीं किया, वाक्यात को सही तौर पर बताया—कि वहां दूसरी कम्युनिटीज ऐसा नहीं होने देते। दूसरी चीज यह है कि दूसरे लोग चाहते नहीं हैं कि ये लोग वहां आयें। वह पब्लिक स्कूल से पढ़ कर नहीं आये हैं, उनकी बुनियादें अच्छी नहीं रहीं। कभी आपने ऐसी इंस्टीट्यूशन उनके लिए तैयार नहीं की जिसमें वह पढ़ सकें, जैसे मिलिटरी के जवानों के बच्चों के लिए आपने सैनिक स्कूल खोल दिये। अगर आप हरिजनों को उठाना चाहते हैं जो कि समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, एक चौथाई या पांचवां हिस्सा उसकी पापुलेशन है, अगर उनको समाज में सबल बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्कूल खोल दें। वह कंपीटिशन में निकल नहीं सकता। हमने बम्बई में देखा कि वहां बच्चों ने वहां की लोकल लेंग्वेज में क्वालिफाई करके मैट्रिक, प्री-मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास करके आये थे, लेकिन इस बिना पर उनको नहीं लिया कि वे अंग्रेजी बोल सकते। एक लड़का हरिजन का एम०ए० पास था, लेकिन उसके अन्दर क्या गुरबत थी कि उसने 300 रुपये एक साहूकार से 20 रुपये सैकड़े पर ले रखे थे और उनमें इस कद्र खौफ था कि जब उसका बास आ गया तो वह हर वक्त घबराया हुआ रहता था, उसका बाप काबलर का काम करता था। इस किस्म के वाक्यात हैं जिससे आप कहते हैं कि 35—40 रुपये में हायर एजुकेशन दीजिए। यह एक मजाक है। आपने कांस्टीट्यूशन में कमिटमेंट किया है, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि जिसमें हर किसी को समान मौका देंगे, तो जिस हालत से आप चल रहे हैं, उस हालत में वह दूसरों के बराबर आयेगा? दो सौ साल तक हिन्दुस्तान के और लोगों के लेवल पर वह नहीं आ सकते। जो वजीफे दिये जाते हैं वह वक्त पर नहीं मिलते। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे इलाके के कुछ लड़के पॉलिटेकनीक में दाखिल होने गये, एक लड़का फर्स्ट डिवीजन पास करके गया था, लेकिन उनको नहीं लिया गया और वापस आना पड़ा और क्लर्क बनना पड़ा।

आपने कहा कि अनटचेबिलिटी के लिए सब कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आयेगी। 25 साल हो गये, अनटचेबिलिटी का कानून पास करके हम बैठे हैं। महाराष्ट्र में, केरल में, गुजरात में हमने देखा कि वह रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं तो वह दर्ज नहीं करते हैं। नहीं करते हैं इसलिए कि जमींदार का प्रेशर पड़ता है। किसी आदमी के खिलाफ शिकायत की जाती है तो पुलिस वाले डंडा लेकर पहुंच जाते हैं कि वह अपने केस को विदड्रा करे या 107/157 में उसको नचाया जाता है। ऐसी आज आपके कानून की हालत है।

आज एट्रोसिटी का जिक्र होता है। जब इन्सानी समाज कानूनी बन्धन से अलग हो जाता है तो एक खूंखार अजदे की शक्ल अख्तियार करता है। पिछली दफा मैंने काल अटेंशन इसी हाउस में दिया था और वह था बलिया डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक लड़की के भाई को दरख्त से बांध दिया गया था और उसके सामने फैलेश्नी किया गया यह कितना अफसोसनाक, शर्मनाक वाक्या हुआ था। लेकिन मिर्धा साहब ने कहा कि हम इन्क्वायरी कर रहे हैं, यह केस जेरे गौर है। इंक्वायरी के बाद कभी भी फोटो आया? सजा दी गई उस मुलजिम को

जिसने किसी मजलूम के साथ ऐसी हरकतें की ? क्या उस को कभी सजा दी गयी ? कभी अखबारात में आया कि उस ने ऐसा किया है ? कितने ही अत्याचार होते हैं उनके साथ, उनके घर जला दिये जाते हैं, वे बेदखल कर दिये जाते हैं, क्या कभी सरकार ने किसी के साथ कोई इंसाफ किया है ? और जो सजा मुकर्रर की गई है उसके लिए वह क्या कभी उनको दी गयी है ? कोई पता नहीं होता। मामले के अदालत में जाने के बाद वह कैसेज दब जाया करते हैं और सारे मामले दबा दिये जाते हैं। तो मेरे कहने का मुद्दा यह है कि यह ठीक है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हमारी प्राइम मिनिस्टर मोहतरिमा चाहती हैं कि इस देश में जितने गरीब तबके के लोग हैं वह ऊपर उठें और वह बार-बार अपनी तकरीर में कहती हैं इसको और वह करना चाहती हैं यह काम, हम इस के लिए उनको मुबारकबाद देते हैं। जैसा उनका खयाल है उसके हिसाब से वह हर जगह चाहती हैं कि उन के साथ इंसाफ हो और जो लोग आप्रेस्ड हैं उन को उठाया जाये और उनकी बेहतरी के लिए वह कुछ करना चाहती हैं, वह ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हैं और आप ने कल अपनी तकरीर में भी कहा था कि आप ने उनके लिए 15 करोड़ रुपया रखा है। यह एक खुशी की बात है बशर्ते कि उस पर अमल हो, लेकिन अगर वह कागजों में ही रह जाय और आपकी बात सिर्फ एलान तक ही महदूद रहे तो उस से मुझे दुख होगा, इसलिए कि वह चीज अमल में नहीं आयी। इसके अलावा मैं कुछ बात अपने इलाके की कहना चाहता हूं, लेकिन पेश्तर इसके कि मैं अपने इलाके की बात कहूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप ने कहा कि आई०ए०एस०, आई०पी०एस० और आई०एफ० एस० में शेड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई लड़का, कोई नौजवान उसमें क्वालीफाई भी कर लेता है तो उसको पहले तो किसी फील्ड वर्क पर नहीं भेजा जाता जिसके लिए वह मुस्तहक है, उसको किसी इंजीनियर पोस्ट पर लगाया जाता है, चाहे वह डाक्टर हो या इंजीनियर हो। पहले उसको किसी एक क्लर्क की जगह लगाया जाता है और उसको फील्ड में नहीं भेजा जाता और अगर वह डाक्टर है तो उसे किसी खराब जगह ही लगाया जाता है। मुझे इसका तर्जुबा है। गुजरात में, जामनगर में एक मेडिकल कालेज है। मैं वहां गया तो देखा कि एक डाक्टर है एम०डी०, एम०बी०बी०एस०, लेकिन उसको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए लगाया हुआ है ताकि उसका तर्जुबा और वसीह न हो सके। इस प्रकार का स्टैप मदरली ट्रीटमेंट उनके साथ होता है। तो वह कैसे तरक्की कर सकते हैं जब तक कि आप की नीयत साफ न हो, आप के विचार साफ न हों, जिनके हाथ में सत्ता दी हुई है, जिनको ताकत दी हुई है जिस को इंसाफ करना है उसको उन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इसी तरह से आप की पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं। आप ने कहा कि उनके बच्चे क्वालीफाइड हैं, लेकिन कितनी ऐसी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं जिन में किसी शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी को आपने चेयरमैन की जगह पर लगाया हुआ है सिवाय एक अंडरटेकिंग के ? जबकि हिन्दुस्तान में 104 अंडरटेकिंग्स हैं, क्या उनके बच्चे क्वालीफाइड नहीं हैं ? आप ने फरमाया कि हमने यह गैप पूरा कर लिया है आई०ए०एस० में, लेकिन मैं समझता हूं कि आप की जो पापुलेशन है कंट्री में दूसरी कम्युनिटीज की और उनके जितने आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आफिसर्स हैं, उनसे आप इनका मुकाबला कर लीजिए कि वह उन के बराबर आते हैं क्या ? लेकिन मैं इन तमाम बातों के अलावा एक चीज हिमाचल के मुताल्लिक कहना चाहता हूं और मैं अपनी बात बहुत जल्द खत्म करूंगा। मैंने पहली दफा भी जिक्र किया था कि हिमाचल में हमारी बदकिस्मती से जब यह रियासत आलमेवजूद में आई तो उस समय यह एक कमिश्नरी सूबा था और यह सेन्ट्रल के मातहत थी। वहां कुछ ऐसी कम्युनिटीज थीं कि जो खानदानी टचेबिल्स थीं और उन्होंने अपने को ट्राइबल लिखवा दिया। और उस कम्युनिटी के लोग हमारे यहां चीफ सेक्रेट्री भी रहे हैं और चार, छः की तादाद में वे आई०ए०एस० और पी०सी०एस० आफिसर भी रहे हैं और वही लोग जितने भी प्रिविलेजज और ग्रान्ट्स मिलती हैं खा जाते हैं। वह लोग तिब्बत के बार्डर पर रहते हैं। 40 फीसदी उनकी पापुलेशन बुद्धिस्ट है और 25 फीसदी हैं हरिजन और वह उनकी मेहरबानी पर जिन्दा हैं और अगर वे हरिजन उन के मकान के सहन तक आ जाय तो उनके ऊपर दंड लगा दिया जाता है और अगर वे बीमार हो जाते हैं तो वे लोग कहते हैं तुम ब्राह्मण के सहन में आ गये, इसलिए हमारा देवता नाराज हो गया और तुम्हें दण्ड देना होगा। तो फिर एक बकरा ला कर के सेगी के

[श्री रोशन लाल]

दरवाजे पर आयेंगे और कहेंगें कि [illegible] बकरा दान में देते हैं,हमारे ऊपर जो कष्ट है वह दूर हो जाय। तो इस किस्म की हालत है। मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से भी इसका जिक्र किया कि हरिजनों की बहुत बुरी हालत है और जो ग्रांट मिलती रही है वह जो आई०ए०एस० के, आई०पी०एस० के या आई०एफ० एस० के आफिसर्स हैं, वह ही अपने लोगों के लिए हड़पत जा रहे हैं। उन्होंने अपनी कोठियां बना लीं। गरीबों को धमकाते है और उनको वह कहते हैं कि मर्दमशुमारी वाले आयें तो ट्राइबल लिखाना और वह हरिजन ट्राइबल लिखाते हैं। हरिजनों की एजुकेशन की हालत वहां यह है कि सिर्फ एक लड़की उनकी इस वक्त छठवीं जमात में पढ़ रही है। जो हरिजन एरिया में रहते हैं उनकी हालत देखी जाय तो इतनी बदतर है। वह लाहोल-स्पीती में भी हैं, किन्नौर और चम्बा के डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। तो आप इसके मुत्तालिक कुछ करें। मैंने इसके मुत्तािल्लक लिख कर भी दिया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो एरिया है उसमें से इस कम्युनिटी को अलग कर दिया जाय और मैं जनाब मिर्धा साहब से बड़े अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि वह इस चीज का खयाल रखें और कोई अमेंडमेंट लायें और इनको उस कम्युनिटी से अलग करें।

P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Hereafter I will give only 10 minutes to each speaker because there are 14 names in the list. We have to finish it today. Shri Schamnad.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala) : I won't take much time.

Let me first draw the attention of this House and the Home Minister to the hill tribes who live in the hilly areas. There are many tribals who live in hilly areas whose very existence itself is not being recognised either by the Government or by the rest of the communities. Recently there was a report in the press, in Malaya-lam papers, and the photos of those unfortunate people also appeared there. Some of them live in the hilly areas of Malabar. They are not voters and they do not have any ration cards. They do not go to any ration shops. They eat fruits, drink honey and live in small cells. They follow the laws of nature. I do not know whether the Commission has noted this or whether the Government have taken cognizance of such people in this country. Have the Government taken any effective steps to bring these people to the main stream of human life? If not, I am sure they will take effective steps at least now. These people live away from the society and I am even told that they are being sold like cattels for labour and other works. I do not know whether the Government has taken note of this.

As far as Harijans are concerned even after 26 years of independence, what we find today is nothing more than what we did find during pre-independence days. Harijans in villages are there where they were. No doubt some of them have become Ministers and risen to high positions. There is no doubt about that. But the bulk of the Harijans, the bulk of these people, has not changed. They continue to be untouchables and they continue to live the same life as they lived formerly. Many of our friends pointed out how they are being discriminated in Government service—right from Central Secretariat service to the panchayat level.

Sir, in the railways where nearly 34 lakhs of employees are employed what is the percentage of the Harijans? If you make a calculation you will know that it comes to nothing. So, Sir, this is a very bad state of affairs which is being continued. What I consider more important than this is the psychological change that should be there in the minds of the people. Superiority complex is prevailing even today in the minds of the upper class people and these poor Harijans are made to feel inferior because of this. The superiority complex of these higher class people creates inferiority complex in the minds of the Harijans. These people should tell the Harijans, "You are our brethren, we are your friends" and so on. This sort of feeling must be there. But it is not there amongst the so-called progressive communities unfortunately.

Then, Sir, you have separate Harijan colonies and you have separate wells for the Harijans. In many villages in the country there are separate colonies for the Harijans. Why do you discriminate against this community and call their colony as the Harijan colony ? Why don t you put them in mixed colonies? Put a Harijan next a Muslim or a Christian and so on. Instead of that, the policy of the Government is to make separate colonies for the Harijans. This policy of bifurcation should be abandoned and these people should be encouraged to come to the mixed colonies and live in cosmopolitan areas.

Another important factor is the prejudiced feelings even amongst the higher officials of the Government. Whatever policies the Government might have, the officers who have to implement them have a prejudiced feeling amongst them also that, after all, these people are Harijans and belong to the backward communities only. This sort of feeling should be abandoned. Sir, to support my view. I would like to quote from an article which appeared in an issue of the "Illustrated Weekly of India," issue dated 22nd April 1973. It is very interesting. I quote from that article

"Some years ago, a leading Congress MP was appointed chairman of a public undertaking with a vast employment potential. Around a nucleus of staff, drawn from the Union Government, the undertaking was to recruit a lot of new people to start a network of projects in different parts of the country.

"With the enthusiastic concurrence of his ICS Managing Director, the MP decided to reserve all Class IV jobs in his corporation for Muslims and Harijans. Within a few days, he had a virtual revolt on his hands. A deputation of officers sent to a remote area to start a huge project came and saw him. They swore that they had no prejudice against Muslims, that they would go out of their way to employ Muslim and Harijan technicians and clerks. But they would not agree to having them as peons at their project. "Why not', asked >e MP angrily. 'Because, Sir, we are working far away from our homes. Who will cook onr meals or carry water for us if not our people 7 Do you expect us to entrust these jobs to Muslims and Harijans? We would rather ask for transfer or even resign and go away.' The poor MP threw up his hands in horror and helplessness."

Sir, do you know who this MP was? He is none else than the late Shri Feroze Gandhi, a prominent M.P. What a state of affairs in the days of Shri Feroze Gandhi who championed the cause of Muslims and Harijans! There is no change today even. This is what I would like to draw the attention of the House too. So, Sir, this feeling is there and this prejudice is there. The higher officials have still this prejudice. Mr. Goray has already pointed out this and done it in nice way. The officers sitting in high positions along cannot do this.

There is need for good social work, a psychological change, a change in the minds of the progressive people, the so called for ward community. They also should feel these people should come to our level. We are brothers and there should be no discri mination. Then only we will be able to do something for these unfortunate Harijans and other backward communities.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Makwana.

SHRI YOGENDRA MAKWANA (Gujarat) : Mr. Deputy Chairman, Sir, we are today discussing in this House a report which concerns one-fifth of the population of this country. Harijans comprise more than one-fifth of our population. But the conditions of Harijans in the villages or anywhere in urban areas remains as it was some 25 years ago. The majority of this community are labourers in the fields. They have no land. They have no money to invest in business, and the land which is provided by the Government in many

[Shri. Yogendra Makwana]

cases is grabbed by the landlords learby. Recently, in Gujarat, the Gujarat Government gave some land to the landless labourers of this community in a village named Kadi, which is in Mahesana district. Some Patels from the nearby fields occupied the landl and did not vacate it. A police complaint was filed. The 'mamlatdar' went there in order to get the land vacated, but in vain. The 'mamlatdar' took refuge in a house, otherwise he would have been murdered. The police was helpless. Ultimately, the question was settled by the Chief Minister with the help of the local Patel community. This is the position prevailing at present in this country.

The policy regarding reservatioins in Government services is also not implemented fully. I have been moving in the Railway Convention Committee this time. In railways, whenever we asked about the roster, which has to be maintained according to the orders about reservations, in many cases it was not maintained regularly. The reservation was not maintained. In the Ministry of Finance also, in the Income-tax Department and at many places the reservations are not maintained properly. In several other cases which are not reported to the Government or to the public workers the same position prevails.

Recently, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes visited the State Bank of India. In their 18th Report, on page 16, it is stated:

"The Committee note with dissatisfaction that although the State Bank of India came into being in 1955 under the State Bank of India Act, 1955. Government orders making reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services were made applicable to the Bank only in 1966...".

Further, it has been stated in the same Report that the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the supervisory staff of the Bank is 0.25 and 0.2 in the Subordinate services of the State Bank of India. Tt is stated :

"In the opinion of the Committee there is a wide scope for appointment of a large number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Their representation is not even 1 per cent."

Further, in the same Report it has been st;ited that in'Calcutta circle it went down to 0.5 per cent in 1965, 0.8 per cent in 1968 and 1.37 per cent in 1970.

This is the position in the State Bank of India, which is a Government concern. In public sector undertakings also the same position is there. If another committee is appointed to investigate, the same thing will come out.

In private institutes, secondary schools and primary schools, this reservation quota is not maintained. Not only that, they harass the persons belong to the Scheduled Castes community. A few days back, I read in the Times of India that a Class I lady officer, namely, Khanpade, of the Directorate of Social Welfare is being harassed by other officers. In I.ucknow, one lady met me. Her name is Ram Dulari Devi. She is doing research in Hindi literature. The Vice-Chancellor, the Dean and the other Professors of the university try to avoid her and harass her thinking that when she becomes a Ph. D., she will sit with them. They are not giving her scholarship. I wrote a letter to the Governor because Uttar Pradesh was under Governor's rule at that time. The Governor marked the letter to the Vice-Chancellor. Some two days back, I received a letter from Lucknow informing me that her scholarship had not been released. That is the condition of the Scheduled Castes and Harijans in universities.

SHRI G. A. APPAN (Tamil Nadu) : Will the hon. Minister take note of these things and give an answer? We do not speak here in the wilderness. The Minister should be attentive. The Minister is not taking nole of anything.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Let him continue with his speech. It is not for

you to take notes. Please take your seat, Mr. Appan.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : The Government claims to have taken various steps for the removal of untouchability and social disabilities. Sir, in this regard I would like to refer to the Report of the Commissioner. While referring to the information furnished by the different j States regarding the villages where untouchability is not practised, the Com-missjoner has made certain comments. I refer to pages 63 and 64 of the Report. Mr. Goray has quoted some portions. I would like to read the whole paragraph so that you can know what is there in the Report.

"The information furnished by the various State Governments excepting Haryana. appears to be doubtful. (.The Commissioner himself says thai the information is doubtful). It is worthwhile mentioning that in Gujarat where a survey on untouchability was conducted by this office in the districts of Ahmedabad and k;iira, the existence of the practice of untouchability was found to exist in the villages covered under the survey, though their names did not figure in the list of villages where prosecution was launched under the Untouchability (Offences) Act. Moreover, the fact that cases were not registered under the Untouchability (Offences) Act, in any village, cannot be taken as a criterion to justify that untouchability is not practised in that village. In reality. there may be hardly any village in the country which can be termed as absolutely free from this evil. The survey conducted by this office in Mysore in 1971 had revealed the existence of untouchability in the villages that had received prizes for doing excellent work for the removal of untouchability in that State."

This is the condition. Further, it has been observed by the Commissioner—1 do not read the para again—that informs- j tion is not correctly supplied by the States. I 1 would request the hon. Minister to impress upon the States to give nroper and correct information to the Commissioner so that we can at least know the gravity of the problem.

Sir, it is alleged that Government servarats belonging to the Scheduled Castes are not up to the calibre which be fits their service and that is why they are not promoted to the higher cadre in the Government services. 1 would request the hon. Minister to arrange training for them. If it is the case and if it is a reality, then we should impart training to these persons so that they can cope up with the other persons. And if training is to be given, it should be given fully. It should not be done half-heartedly. If it is done half-heartedly. then we will lose social mobility by leaving them on half way. And we should impart training in such a way that they come out as finished products and thus help the society.

Sir, so far as the economic measures taken by the Department of Social Welfare are concerned, they tire not fully implemented. So, a committee should be appointed at every level comprising of some social workers who can look after the work done by the Social Welfare Department. Sir, in the States, the portfolio of Social Welfare is always given to a junior Minister, who has no say in the Government and who is not even respected. I know some of the Ministers who are not even respected by the officers. They say : "sfr^Rf TT DtPTW* ?., Tto *m?Tr §" That is what is going on. This portfolio should be handled by the Chief Minister of the State. If this is done, then I do not think any officer will dare to disobey the instructions issued by this Department.

Sir, everyday we read in newspapers about the atrocities committed on the Harijans in different villages and in different parts of the country. My hon. friend has quoted from the Illustrated Weekly which says that officers are not prepared to accept water from peons belonging to the Scheduled Castes. That is the condition prevailing even today. So

[Shri Yogendra Makwnmi]

far as the atrocities are concerned, there was an article in the Times of India Weekly—I do not have the date here— wherein the author has cited the Minister of Home Affairs, who replied in this House on 18th August, 1970. The Minister told the House that 1,112 murders of Harijans were reported to the Authorities in 1967-68. Sir, I would like tc read one para of this article.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You have no time. You can just mention it.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : It has been mentioned in that article that in Uttar Pradesh, some Scheduled Caste students were murdered in a hostel and the Authorities have not done anything in this regard. I would, therefore, request the hon. Minister to give strict instructions to the State Governments and to various Departments to follow strictly the instructions issued by the Minister of Home Affairs from time to time. Thank you, Sir.

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल (बिहार) : उपसभापति जी, अभी हाउस के सामने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट उपस्थित है और इस पर दो दिनों से बहस चल रही है। साथ ही साथ मैं जिक्र कर देना चाहता हूं कि कमेटी आन वैलफेयर आफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 20वीं रिपोर्ट छप चुकी है। इन सारी रिपोर्ट्स को देखने से मालूम पड़ता है कि हरिजनों के संबंध में संविधान में जो कुछ प्राविजन किये गये हैं या जो कुछ भी सजेशन कमिश्नर की तरफ से आये हैं या वलफेयर कमेटी की तरफ से आते हैं, उन सब का जो असर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ना चाहिए, वह असर नहीं पड़ पाता है। गवर्नमेंट का जो आर्गेन है उस के ऊपर असर क्यों नहीं पड़ पाता है और समाज में जो स्थिति हरिजनों की या आदिवासियों की शुरू में थी, उस में कोई सब्सटेंशियल परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है? इस बात को पकड़ने की जरूरत है और इस पर सोचने की जरूरत है। मैंने जैसा अनुभव किया है वह यह कि हिन्दुस्तान का जो समाज है यह समाज जिस ढंग पर शुरू से बन चुका है वही इसका कारण है। यह समाज बना था बहुत पुराने जमाने में जब कि शोषण जाति प्रथा के रूप में होने लगा था, उसके लिए जाति का एक इंस्टीट्यूशन बना था और उसी समय समाज दो टुकड़ों में बट गया था। एक टुकड़े में वे लोग थे जिन्होंने शोषण करने का भार अपने ऊपर लिया था और जिन लोगों का शोषण किया गया था उन लोगों को देश के इंतजाम के भार से अलग कर दिया गया था। शोषण भी किस ढंग से किया जाये इस का दायरा भी अलग-अलग कर दिया गया था। सांस्कृतिक शोषण किस प्रकार से किया जाय, आर्थिक शोषण किस प्रकार से किया जाय, राजनीतिक शोषण किस प्रकार से किया जाय, उस के लिए सारे इंस्टीट्यूशन्स अलग-अलग कर दिये गये थे। इसी की तरफ से अगर जाति प्रथा का विश्लेषण किया जाये तो आप को साफ मालूम पड़ेगा कि जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था में निहित था कि आर्थिक शोषण कैसे किया जा सकता है और सब मिल कर सामाजिक शोषण कैसे कर सकते हैं। यह सारी व्यवस्था उस समय कायम हो गयी थी। उसके बाद, हिन्दू राज के बाद इस देश में मुसलमान राज आया और फिर अंग्रेजों का राज आया और अब यहां कांग्रेसी राज चल रहा है, लेकिन देश की जो लीडरशिप बड़ी जाति वालों के हाथ में आ चुकी थी, उस में थोड़ा बहुत फर्क आया था मुसलमानों के जमाने में और फिर अंग्रेजों के टाइम में भी उसमें थोड़ा बहुत फर्क आया था, थोड़ा बहुत परिवर्तन इस कांग्रेसी राज में भी आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, लेकिन सब्सटेंशियली जो नेतृत्व देश का उस समय में था, वही नेतृत्व आज भी समाज में मौजूद है और यही कारण है कि आज का जमाना केवल इस मायने में बदल गया है कि सारे संसार में आज जनतंत्र का विचार और समाजवाद का विचार एक जगह पा चुका है और सब जगह यह विचार विजय पा चुका है। विचार रूप में यह दोनों आइडिया विजय पा चुके हैं। इसलिए आज के समाज में अगर कोई बात कोई समाज या व्यक्ति करना चाहता है तो इन दोनों के विरोध में वह कोई बात नहीं कर सकता। इस एटमास्फियर का प्रभाव उनके ऊपर पड रहा है, लेकिन चूंकि दिल से वे इस विचार को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए उसका नतीजा यह होता है कि लुकाछिपा कर इस ढंग की नीति, इस तरह के कानून बन जाने पर भी कि उन का शोषण न हो सके, उन पर अमल इस तरह से किया जाता है सरकार के जरिये और समाज

में जो दूसरे लोग हैं उन के जरिये इस ढंग से उन का आपरेशन होता है कि पुराने समाज में जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे यह कानून उन को उखाड़ नहीं पाते। पुराने समाज का जो प्रभाव है वह उखड़ नहीं पाता और उसका प्रभाव सरकार पर से कैसे उखड़े इस प्रश्न पर ही हम को विचार करना है, उसका ही उपाय सोचना है और इस सिलसिले में जो जाति नीति के संबंध में जो अभी तक हम लोगों ने प्रचार किया है उस को भी मैं इस सभा के सामने लाना चाहता हूं। आज जो मिश्रित सरकार चल रही है उसमें अधिकाधिक संख्या उन लोगों की है जिन लोगों ने शुरू से राजपाट हिन्दुस्तान का चलाया है। जो पावर है, गवर्नमेंटल पावर है उसमें जब तक चेंज नहीं होगा तब तक समाज में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए समाज को भी बदलने के लिए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बदलना होगा और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बदलने का मतलब होगा कि जो अपर कास्ट की अधिकता एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको कम करना पड़ेगा और उसके स्थान पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का परसोनल है उसमें जिन लोगों का हजारों वर्षों से शोषण हुआ है उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की ऊंची से ऊंची जगह में रखना पड़ेगा। यह निश्चित है कि हजारों वर्षों से उनको महत्व न मिलने की वजह से वे सक्सैसफुल एडमिनिस्ट्रेशन पूर्व नहीं कर सकेंगे, लेकिन वे गलत-फलत करते हुए वे अपने स्वार्थ का एडमिनिस्ट्रेशन जरूर बना लेंगे। एक बार एक आदमी ने हम से पूछा कि आप बहुत जाति-नीति की बात करते हैं। आप यह भी कहते हैं कि अगर आप अयोग्य आदमी को लाएंगे तो उसको बहुत बड़ी जगह पर लगा दिया जायेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिया जायेगा और अगर ऐसा किया जायेगा तो आज के एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा? पहले तो मेरा भी दिमाग चक्कर खाया। लेकिन फिर भी मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आज जो एडमिनिस्ट्रेशन इस हिन्दुस्तान में चल रहा है क्या आप उससे सन्तुष्ट हैं? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हम सन्तुष्ट नहीं हैं। हमने कहा कि आज जो बड़ी नौकरी की जगह हैं उसमें भर्ती करने की क्या प्रणाली है? तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जरिए होती है। हमने कहा कि पब्लिक सर्विस कमिशन में जिन लोगों को लिया जाता है, उसमें आप यह समझते हैं या नहीं कि देश के जो बैस्ट ब्रेन हैं उन लोगों को इसमें लिया जाता है। हमने कहा जब देश के बैस्ट ब्रेन को लेकर कामकाज हिन्दुस्तान का चलाया जाता है तो इस एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों आप सन्तुष्ट नहीं हैं। तब वे चुप हो गये। तो हमने कहा कि यहीं पर हमारी जाति-नीति आती है।

जो लोग अभी राजकाज चलाते हैं उनका स्वार्थ है समाज में और ऐसे लोग जिनके ऊपर जो शासन होता है उनके स्वार्थ में वह टक्कर खाता है। टक्कर इस मायने में खाता है कि जमीन किन्हीं के कब्जे में है, कारखाने किन्हीं के कब्जे में हैं, बैंक्स किसी के कब्जे में है और यह जो इंस्टीट्यूशन्स हैं और जो इंस्टीट्यूशन्स समाज के धन के साधन हैं वह किसी के कब्जे में हैं और उन इंस्टीट्यूशन्स का प्रभाव किन लोगों के ऊपर पड़ता है, जो मजदूर हैं या ऐसे लोग जो नीचे के हैं उन पर पड़ता है। और दोनों का स्वार्थ एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है। वे यह समझते हैं कि कितना काम पाने से हम को मुनाफा होगा। वे यह समझते हैं कि कितना बेसिक पाने से हमको मुनाफा होगा और इस तरह से स्वार्थ का संघर्ष हुआ करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी तकलीफ को जितना समझना चाहिए उतना नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है कि हिन्दुस्तान में जो समाजवाद की बात उठी है वह सफल नहीं हो पाती है। जनतंत्र भी आज सफलता-पूर्वक नहीं चल पाता है, उसका कारण है कि जनतंत्र को चलाने के लिए समाजवाद की नीति को सफल करने के लिए जैसे नेतृत्व की जरूरत है, वह नेतृत्व नहीं है।

एक मर्तबा हम से पूछा गया कि अगर एक मुसहर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो क्या नतीजा होगा? वह मुसहर अगर कुछ नहीं करता केवल खेत-मजदूरी करता है तो कम से काम इतना तो करेगा प्राइम मिनिस्टर हो कर कि अपना और अपने परिवार का पेट भरेगा। उसके जो जाति के दूसरे लोग हैं उसका पेट भरने की कोशिश करेगा। उसकी वाह-वाह लेने की कोशिश करेगा। ऐसा उन्होंने कहा। आज हिन्दुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जिसे अच्छा कहा जाये, बैटर कहा जाए।

आज जो हिन्दुस्तान के पिछड़े समाज के लोग हैं। जो मुसहर क्लास के लोग हैं, जो खेतिहर मजदूर लोग हैं उन लोगों का पेट भरे, उनको थोड़ी जमीन मिले, उनकी थोड़ी मजदूरी बढ़ जाए और इससे भी बढ़

[श्री भुपेन्द्र नारायण मन्डल]

कर अच्छा काम अगर होता है तो वह हिन्दुस्तान के लिए अच्छी बात होगी।

हम सोचते है कि आज अगर कुछ करना है तो समाज में जिन लोगों के हाथ में असल शक्ति है गवर्नमेंट में रहने के नाते, अखबार की मोनोपाली अपने हाथ में रखने के नाते या जो भी इम्पोर्टेन्ट चीज आज समाज में है उसका नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है, कब्जा जिन लोगों के हाथ में है, उन्हीं की वजह से कुछ कर सकते हैं और उन्हीं की वजह से समाज ठीक से नहीं चल पाता है।

इसलिए हम समझते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है इसको इस लाइट में देखिए कि क्यों फेल्योर हो रहा है, क्यों सक्सैसफुली काम नहीं हो रहा है, उनकी दशा में क्यों नहीं सुधार आ रहा है? क्यों इनके सजेशंस को नेगलेक्ट किया जाता है? तो इन सारी बातों की जड़ में यह बात है ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए, मेरा सजेशन है कि जो मैंने कहा है उसको मंत्री जी समझेंगे और जब कि सिविल सर्विसेज का रिआर्गेनाइजेशन करें तो इसमें इस बात का ख्याल रखें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The hon. Home Minister will intervene.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI UMASHANKAR DIKSHIT) : Mr. Deputy Chairman, I had not originally intended to intervene in this debate. My colleague who has been handling this subject generally, both in the Department and in Parliament I had depended upon him to express the views of the Government in this House. But a colleague, a friend came up to me and suggested that it would be very much ir the fitness of things that I should also participate in this debate and 1 gladly accepted this suggestion.

SOME HON. MEMBERS : Very kind of you.

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT : I do not think T am obliging anybody. 1 now think 1 would not have done my duty if I had not given some expression of the deep feeling, of the deep sense of discontent, of spiritual discontent, of almost a guilty feeling on behalf of the society we represent, if I had not taken advantage of this opportunity to express my views and feelings before this House.

Sir,/ the last speaker Shri Mandal has made a very valid point. He has suggested that Government should go into this question deeply to find out why* despite various measures that have been taken from time to time and the conviction that is shared by all sections of che society, and all sections of this House, still we are not succeeding and the progress is slow. I agree with him and I think it is the duty of the members of this House from all parties, both official Benches and non-official Benches, not only at this time in this House, but 1 think we should seek some separate opportunity of going into the depth and detail of the various problems that are begging solution.

Now, Sir, I rapidly went through the Report and studied some of the appendices; and in the very first chapter which is a general review of the various measures taken, some successes achieved and failures* faced, I find this sentence in the very first page A sense of insecurity and economic helplessness appears to be deepening in their minds " that is the minds of the Scheduled Castes and Sche duled Tribes—bringing in its trail . a feeling of minority insecurity." This feeling of helplessness is not only being felt by the people who are suffering under various handicaps among Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but 1 believe all men of goodwill, all patriotic Indians, all Indian men and women who have some faith in the destiny of this country, are having a feeling of helplessness. Now going through the Report I have found that in the various Departments of Government, the Central Government and the various State Governments have undertaken a very large number of measures of social amelioration, of prevention of un-touchability, of improving economic and social conditions of the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and so on. The feeling that I referred to just now which one gets at the end of

the Report is that while qm'te a lot of effort is being attempted the result is not commensurate with the desired objectives, with the professed desires and with ill the expenditure that goes to run these Departments. Sir, I shall not try to blame anybody as Minister of Home Affairs w 10 now shares the responsibility at the Centre for a part of the Social Welfare Department's work; but I have, no hesitation in saying that we have a very long distarce of the journey we want to travel and it will require much greater measure of devotion, of continued patience, devo! ;d labour, to achieve the objectives to wh ;h we are committed and before we can cla m to have achieved anything like a sa'.s-factory measure of social welfare.

I find that if all the most import; nt matters that are being dealt with the ecu-cation side has attained a certain measvre of success not only in primary education but in the matter of higher education al o. It has resulted in improving the perce it-age of literacy both among Schedu :d Castes and Scheduled Tribes. Though t lis percentage of literacy is less than the ge e-ral percentage of 29 for the who'e coun y still it has im, roved very considerably in the last 15 yea s. Similarly in higher c u-cation 10 which very considerable str ss has been laid by gVng post-matric scholarships, we fine' th; in that din etion a!so we can express a certain amour l of sa is-faction over the fa that the number of post-matric scholi lips, post-gradmte scholarships have :n from about ' A'o or three thousand to nearly 3 lakhs. 3y the end of March 1973 the number of Scheduled Caste scholarships had risen to two lakhs and for Scheduled Tribes he number had risen t :> about 35,000. And by this time, accorc'ng to informat on available with us, it appears that the nim-her has nearly reached 3 lakhs. This in my opinion is a foundational effort. I ay this because, as Mr. Mandal and other * friends have pointed out, there is a long history of 500 or 1000 years behind it which has reduced a part of our society to such backwardness and degradation. It is no use now blaming the ancients. Possibly

the system that they then evolved answered the requirements of that age. The entire caste system, the Varnashrama Dharma nas since completely outlived its utility. It is it the process of breaking down. Tneiu is hardly any pr fession which is now beinw. followed by the caste people accordms to the criteria or the religious tenets laid down by the ancients. Members of the Harijan co nir nity are working in tne Defence depar : lent. Some of them arc carrying on small businesses. Mary others are, in religious and spiritual matters, as highly respecte and some of them more highly respected than the other caste men or women. Similarly, in other professions, for instance, 1 do not think there is even itn per cent of Brahmir.s today who would be following the profession specified for Brahmins as a caste. 1 need not labour this point. I believe Members of this House will accept the fact that as a result of the impact of modern conditions and the rapidly changing economic and social conditions ir this country and in the rest ot the world, this outmoded system is in the process of brewing down. It will not be long before the core of that system may be completely ended. It appears to be doomed so far as the future is concerned. So far as the general social conditions are concerned, my personal hope is that the social status or the Harijan community and the tribal communities will gradually improve. Because of their position in the various legislatures, both Central and State legislatures, and other public bodies, their social sta as has already acquired a certain position of equality with the other castes. It is in the economic field that the situation has its weakest point. Now, several suggestions have been made by hon. Members. I hope my colleague will deal with them one by one. Where specific instances have beer, pointed out, I shall give my personal attention so as to examine the various measures suggested here and see what can be done within the resources available and within the legal and other constraints to which we are subject.

I find that employment, for instance, is the greatest need of the hour and it is

[Shri Umashankar Dikshit]

creating a lot of helplessness and frustration among the members of the Harijan and other communities. Ii is in a bad way. So far as the private sector is concerned in most places members of these communities get very few employments. The only hope, in my opinion, is in the direction ot the public sector. While instructions have been issued from time to time and tho policy has been explained to the managing directors and chairmen of public bodies, it is a sad fact it is a matter of shame. in my opinion, that even in respect of new employment this policy is not being adequately followed, if you go through the report, particularly the Appendices, you will find that if there is, comparatively speaking, any sizeable number of employments given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes members, it is mostly in the public sector and undertakings and Government departments. Therefore, we should present this as an example for others in the private sector, in the State departments. Unfortunately, I am sorry to say, that not all the State Governments seem to have given it that measure of serious attention and importance which this subject really deserves.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): May I only interrupt you for a moment'1 This policy can be adopted in the private sector also where the financing agencies can put a condition that so much employ ment must be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. In th< public sector it is there. It can be done il you cam take it up with the Finance Minis ter.

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: At idea has been suggested here that a Cor poration may be set up with Rs. 1,001 crores. That is a large amount. I do no wish to hold out false or unpractical hopes

SHRI A. G. KULKARNI: It can D done through financing agencies like natic nalised banks, the LLC. and so on.

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT That is true. 1 would like to poir.t ou that we begin with the professions which the'riembets of these communities would be aggreabfe and well-inclined to take immediately and successfully.

One hon'ble Member yesterday suggested that mors sophisticated business, industries, distributing processes should be made available to these communities. It is true 'hat a small number of them have developed adequate capability to be able to handle such professions. But it may be more important at present firsl to give them education and then to find employment which they can take up immediately. In the various services, class IV, class III and class II, at least these three classes, they could have more adequate measure of representation than what it exists now. Under no circumstances should we allow their representation to fall below their popula-tional proportion. So I was saying that so far as the ptiblic sector undertakings are concerned and the State Government departments are concerned, it should be our endeavour, and it will be my endeavour, to see that their employment therein increases. Of course, it has to be gradual. It can be in a large measure where new departments are opened, new sections are opened, r.evv undertakings are started. Where already large undertakings have been existing for many years it is not possible to induct very large numbers of Harijans or others.

Now. in the matter of land and agriculture, this is another field where more than the Central Government the State Gov-eir.ments can really show appreciable results if serious attention is devoted immediately. I must say that the progress achieved hitherto is very pi

There is, as the other Members have pointed out, a very hostile and unsympathetic atmosphere prevailing all round particularly because in the existing conditions of ecomonc scarcity and stringency and unemployment there is a race, almost rivalry, not only between Harijans and non-Harijans but between non-Harijans and non-Harijans separately also. The result is that due to the influence that the so-called higher castes are able to exercise over the

governmental machinery and the leaders in the States, that measure of support to the Harijans which we want to achieve as quick y as possible is not being successfully attained.

So far as agriculture is concerned, 1 have no doubt that now that the land reform measures have been finalised in most of the States, surplus land is going to be available. It may be in small measure in some States and large in other States. But there is certainly going to be some surplus land available which will be over and above the ceiling which has been prescribed in the land ceiling Acts passed by various States. Except in two or three States, these Acts have already received the assent of the President and they are now in full operation. In my opinion, the test of the professions of these Governments and the Centra! Government and the party I represent will lie in the success that they achieve in distributing whatever land is available spsci: lly to harijans and tribals. It may not be sufficient for all the poorer sections of the community. There are backward sections and poor sections almost in all caste:. It will not do if we equitably give it to all castes. It will be necessary, and I thirk it is our duty and the duty of the State Governments, to take sides with the supp ssed communities. Personally I have ibt that an honest and earnest effor will : made by the State Governments tc make surplus land available primarily tc men ers of the Scheduled Castes anc Scheduled Tribes.

So far as the social status is concerned, 1 would again say that until the Scheduled Cast . particularly, are rid of the degrading professions to which they are subjected, il will take a very long time and it will be exceedingly difficult to raise their status reall, to that of equality with the othei castes. And the worst of them, to whict there is really no adequate answer, is tha of s avenging. It has been suggested hen and it has been suggested at other forum; that if we provide them with handcarts then the sweepers will be rid of this prac tice of carrying nightsoil over their heads 1 am afraid this is no solution. I have trie< it here in Delhi itself. I di tributed a few hundred hand-carts for th purpose. But then their loaders came to me and said, "What shall we do with this in Old Delhi?" Nightsoil accumulates in tin upper floors — the first, second and third floors—and there is no mechanical or other method by which it can be brought down below, with the result that these men and women have to climb up and carry all this dirtv-smelling material from the i :cond floor and first floor, down to the g ound floor. So between doing that and pitting it into the cart and cat tying it. there s not much of a difference. I think it is he duty of the research institutions attached to Social Wel fare to find some other ways. Of course, the only real known meiTiod which in course of time is going to succeed is to introduce the flushing sysUm. Of course, now there is a let of talk about water being polluted by nightsoil

4 P.M. thrown into the various rivers of the country. Some way will be found to see that the prob lem of river waters being polluted by nightsoil is tackled in future. So also, 1 hope, some way will be found to tackle his particular problem. But personally 1 have no doubt that the only way that Gov ernment agencies and private voluntary agencies can help is by putting pressure upon landlords, municipalities, to remove the present and wro! of ollection of nightsoil and to introduce, instead, the system of flushing the nightsoil, so that when the time comes for this community to declare once and for a'l (hat they arc not going to carry on this profession, thereafter, then at least, major conflict would be avoided. And ! do hope that | the day will come, not in the distant future, when the men and womn belonging to this scavenging profession ii declare that under no circumstances are they going to participate in this degrading profession. Today the greatest trouble that arises in this context and in connection with other problems that have arisen in the recent years, is the fact that the society as a whole is not taking sides with the Harijan . community and with the tt ibal people. Not

[Shri Uma Shankar DikshiU

only the men in public positions, Ministers, Members of Parliament, Members of State Legislatures, heads of departments in the police, in the administration, whenever a report is received that some atrocity is committed, some injustice is done to an individual or a group of people belonging to the Harijans or the Adivasis then everybody should give up all other work and rush to the aid of these people. Even if the person in authority does not do so, but a public man of some position like anyone of us rushes to the spot and makes enquiries. If that act has not been committed but has been threatened to be committed, then you prevent it. Or if it has already been committed, then you create an atmosphere and put to shame the perpetrators of such injustice and make them apologise and take a kind of pledge not to resort to such tactics in future. What is necessary, in my opinion, along with official activity, along with legislative measures which have been passed from time to time, is readiness on the part of the society and its responsible men and women in public positions, in public life, set an example and intervene and take sides with the oppressed and with the parties against whom this kind of injustice is being committed from time to time. I shall not take more time of the House. In my opinion, after the visions of the Prevention of Unto Act have been strengthened, and < measures which have been referred t< in the Report before the House have been decided upon, it should be the duty of the Central and State Governments to meet together through their representatives and arrive at a plan of simple action, a time-bound action, to be undertaken in the various States. We are doing so many things at the same time that I am afraid we are not able to give adequate attention to each of them separe-tely. On the other hand, if through semiofficial or semi-public society we undertake some of these measures and if an amount of co-ordination is achieved between governmental activity and private social activity, then I believe that the present position of helplessness cm be corrected in a reasonably short time, fairly effectively.

SHRI B. T. KEMPARAJ (Karnataka): Sir, . . .

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra) : It has been pointed out that there is no representation in the public sector...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Wc arc not going to have a cross debate. I have called Mr. Kemparaj. You cannot raise a discussion now.-

SHRI B. T. KEMPARAJ : Mr. Vice-Chairman. I want to place on record my appreciation and also my congratulations and thanks to the Minister of Home Affairs for having brought the Commissioner's report for discussion on the floor of the House.

Similarly, I also thank the Commissioner for having undertaken a very difficult task on his shoulde s and giving an account of the work that has been carried on at the Cent ;l and State levels. The points which ha i e been ', .ist now referred to by the hon. Minister for Home Affairs clearly go to show as to how the minds of the younger generation among the Harijans and Girijans have been working.

[The Vice-Chairman (Shrimati Purabi in the chairj

ological aspect of this im- portai .vhich is lurking in the minds of caste lindus as well as Harijans should also be considered. If a research has to be made ,n this behalf, it is also welcome.

Accord ng to me, after the Constitution was promulgated on the 26th January, 1950, the word 'suitability' was invented as far as services are concerned. This word 'suitability' has gaily hampered the progress of Harijans and Girijans and has come in their w;:y of entering Government service. Though the Harijans feel confident of their own ability, their own ace and their own efficiency in the ield in which they are sure of faring

well and discharging their duties properly and efficiently, the people or officers who have to select them very often point out that they are not suitable. As a matter of fact article 335 of the Constitution contemplates only efficiency in adminis-tion and fulfilment of qualifications. These are the two considerations which should govern the eligibility of Scheduled Castes and Tribes to Government service. A matriculate who has 40 per cent marks has to undergo a test if he wants to become a second division clerk. Though he passes the test, in the viva voce test he will not be allowed to pass, the simple reason being that he is not eligible to get into the service because he is not suit-able. Therefore, wh it I want to say is that the only remedy lies in giving a greater considertion, greater scope and greater chances to these candidates who are considered ineligible and unsuitable according to the estimate of the officers concerned who think that though these people are not suitable, they would become suitable if proper op, urtunities are given to them. At least this is true as far as the Harijans and the G'rijans are concerned.

Now, Madam, I come to the other aspect of the question, the question of untoucha-bility. Now, Madam, untouchability is being practised between communities and com-munities, between castes and castes and between sections and sections. Why is it that untouchability is so glaringly manifest or so glaringly visible in -the case of the Harijans and the Girijans only ? The Giri-jans are kept in secluded areas and the Harijans are always kept away from the main villages. That was the reason why Mahatmaji had to t; ke up the cause of the Harijans and startet' living actually in. the bhangi colonies and tried to live with them and understand their feelings and also tried to make the other Harijans know how to live in these colonies and in the Jhonpris and he also tried to enlighten them about the surroundings and environments amidst which they were living Sir, while the Mahatmaji drew the attentior of' the people of the entire nation to fh< conditions of these forgotten, forsaken and ignored people called the Harijans, I am continuously in touch with the Harijans, with the Harijan welfare work and also with the caste Hindu people. Madam, the Government has been doing its best. Indeed, they have been trying to do more. But it is found that though help has been given to these people, in between there is some loophole and in the middle there is so much of wastage which fact is not given serious thought to. That is why the problem of the Harijans and the Girijans could not be solved in the way in which we want or we desire.

Madam, I had the opportunity of being a member of the Mysore Legislative Assembly as early as 1952. I was the first to get the Harijans some land. I got my father-in-law's land sold and acquired other plots for the purpose of formulation of a colony where all sections of the Harijans have been housed. It is a composite colony. There is also the drinking water facility for all these people and we have the improved systems of toilet there, that is, we have the pit system there. I got soacking pit system of lavatories dug in many villages. This will work more effectively and efficiently than the system in which the scavengers have to carry the loads on their heads. So, Madam, examples are there in plenty of schemes worked out and implemented and carried out fully. Therefore, Madam, it is not difficult to see that some measures are adopted to do better justice to the Harijans and the Girijans.

Then, Madam, as far as the other questions are concerned, the housing problem is there for the Harijans and it is a problem which has been tackled at various levels and at different times. And, Madam, a great deal has to be done to achieve the target and to see that the Harijans and the Girijans are housed properly. Madam, whenever sites have been distributed for Harijans and Girijans, the Harijans or the Girijans have been forced often to sell away their house sites for the caste Hindus at cheaper rate. I Again, the same crowd of Harijans come; j forward for further acquisition of land I Therefore, it is necessary for us to thinl

[Shri B. T. Kemparaj]

seriously how far when once the Harijans or the Girijans are given house sites their sites should not be alienated for anybody . . . (Time bell rings). These sites should not be alienated for a fixed number of years. These should continue to be i the property of the family for ever. If such a stringent measure is brought, then only ! we can feel that whatever the Government will do to house these houseless people will be in their possession ; they will be having at least the houses to live is whereby they will have a better chance of living. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Mr. P. S. Patil.

श्री पंढरीनाथ सीतारामजी पाटिल (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदया, भारत सरकार की आदिम जाति और वनजाति विभाग के कमिश्नर की रिपोर्ट आज सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है और उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

अपने देश में इन जातियों की जनसंख्या करीब 21 प्रतिशत से भी ज्यादा है और इन लोगों का इतिहास जो है वह यह बतलाता है कि ये लोग सदियों से पिछड़े हुए आये हैं और तरह-तरह की गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। चार हजार वर्ष पूर्व जब आर्यों ने इस देश में आकर अपना राज जमाया तो यहां पर जो मूल निवासी थे उन्हें पराजित होने से भागना पड़ा। तब इन्हें अनार्य कहा गया था। ये लोग आज भी जंगलों में रहते हैं और आदिवासी के नाम से पहचाने जाते हैं। अपने को स्थिर होते ही आर्यों ने अपना चातुर्वण्य अनार्यों के ऊपर थोपा और स्वयं उच्च वर्ण बन बैठे। जिन आदिवासियों ने आर्यों के पास शरण ली उन्हें क्रमशः क्षत्रिय और वैश्य बनाए और जो अनार्य अनेक वर्षों तक लड़ने के बाद आर्यों के शरण में आये उन्हें शूद्र अथवा अस्पृश्य बना दिया तथा गांव में जगह न दे कर उन्हें गांव से बाहर रहने के लिए जगह दे दी। तथा उनके जीवन के जितने भी साधन थे वे उनसे छीन लिये गये। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी आज वे सब जगह पर पिछड़े हुए हैं। इतना बड़ा देश जो हमारा है उसका अगर एक अंग जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, वह कमजोर रहता है, तो वह देश बहुत ज्यादा दिनों तक स्वतंत्र नहीं रह सकता है और न ज्यादा तरक्की ही कर सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में जाति भेद व छुआछूत का भेद-भाव पैदा हो गया है और उस का जो दुष्परिणाम हुआ है उसका इतिहास बहुत रोमांचकारी है। मैं सदन का समय इस चीज को कहकर यूंही समाप्त करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अछूतों के ऊपर जो जुल्म होते आ रहे हैं, उसको हम आंखें खोलकर नहीं देखते हैं। हमारे देश में 12वीं सदी में मुसलमान लोग थोड़ी संख्या में आये, लेकिन आज वे करोड़ों की तादाद में हो गये हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। उनमें से कुछ लोगों ने फूट कर देश के दो टुकड़े किये, भारत व पाकिस्तान। यह किस बात का परिणाम है ? यह परिणाम इस गलती का हुआ कि हम लोगों ने अछूतों को तरह-तरह के जुल्मों से सताया और फलस्वरूप वे असंख्य लोग इस्लाम धर्म में चले गये। स्पष्टतः जाति-भेद से धार्मिक और सामाजिक रूप से असीमित नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, अगर हम इतिहास को देखें, तो हम यह पायेंगे कि हम लोगों ने अपना स्वराज्य इन अछूतों के कारण ही गवां दिया था। मैं उस इतिहास का नमूना पेश करना चाहता हूं। जब सोलहवीं शताब्दी में यहां पर मुगल बादशाह मराठों से पराजित हो गये, अगले कुछ वर्षों में मराठी स्वराज्य कन्याकुमारी से लेकर पेशावर में अटक तक था। तब इस काल में मराठों के जो पंत प्रधान थे पेशवे, उन्होंने अछूतों के साथ भारी छल शुरू किया उनकी छाया से भी वे विचलते थे। पेशवों के जाति-भाई अछूतों को गांवों में भी आने नहीं देते थे। और न ही उन्हें जमीन के उपर थूकने का हक था। उनकी पीठ के पीछे झाड़ू बंधी रहती थी ताकि रास्ते पर चलने से उठे हुए उनके पैर के निशान मिट जायें। इस तरह उन पर भारी जुल्म किया गया। मराठों में आपस में झगड़े और दुश्मनी शुरू हो गई तो उसका फायदा अंग्रेजों ने लिया वे महाराष्ट्र के ऊपर फौज ले आए। अतः जब

अछूतों ने यह देखा कि अंग्रेज आ गए तो जो हमारे साथ छल चल रहा है और जो हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है वह दूर होगा और उनके राज्य में हम सुखी होंगे । तो उस वक्त कोरे गांव नामक जगह पर अंग्रेजों की फौज से महरों की फौज मिल गई और उन्होंने मराठों को हरा दिया । इस तरह राजनीतिक क्षेत्र में जो अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी उसका मुख्य कारण जातिभेद और अस्पृश्यता है । इतना होने के बाद भी हमारे देश की आंखें अभी तक खुली नहीं हैं । लेकिन महाराष्ट्र ने जरूर इससे सबक सीखा है । उस वक्त से महाराष्ट्र में इस बारे में बहुत कोशिश हुई है । इसका बड़ा इतिहास है । सवा सौ साल से महाराष्ट्र ने अछूतोद्धार के बारे में जो काम किया है और जो अच्छे-अच्छे नतीजे पेश किए हैं देश के सामने उनकी तरफ भी चलते-चलते थोड़ी नजर डालनी चाहिए । पूना शहर में महात्मा ज्योतिबा ने 1848 में महिलाओं के लिए और 1850 में अछूतों के लिए स्कूल खोले और अपने देश में अछूतों और महिलाओं की शिक्षा आरंभ हुई । उसके बाद छुआछूत नष्ट करने के लिए महात्मा फुले ने बहुत कोशिश की । उन्होंने गुलामगीरी नामक पुस्तक सवा सौ साल पहले लिखी, जो उस वक्त पब्लिश हुई और उसका अंग्रेजी में भी भाषान्तर हुआ जो आस्ट्रेलिया जैसे देश में उस जमाने में उसका भाषान्तर किया गया। उसके बाद कोल्हापुर के शाहू महाराज ने अछूतों का अखिल भारतीय संगठन किया । डा० अम्बेडकर ने कितना बड़ा काम किया । उन्होंने अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए महान संघर्ष किया है । वह बहुत से सभासद जानते हैं । स्वराज्य मिलने के बाद भी यशवन्त-राव चव्हाण जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अछूतों के लिए देश में पहले स्कालरशिप शुरू की, उनको नौकरियों में सुरक्षित जगह दी । आज के चीफ मिनिस्टर श्री नाइक भी इसी तरह से काम कर रहे हैं । उन्होंने जिले-जिले में इस काम के लिए समितियां कायम कर दी हैं । इतना सब होने के बाद भी मैं महाराष्ट्र की दो घटनाएं आपके सामने रखता हूं । एक एरन्ड नामक गांव की है । वहां स्पृश्य हिन्दुओं और सरकारी अधिकारियों ने मिल कर एक अछूत को देवता के सामने बलि दे दिया । और दूसरे जहां मैं रहता हूं, चिखली नाम के गांव में, वहां से केवल 8 मील की दूरी पर एक कोले गांव नाम की जगह है वहां स्पृश्य हिन्दुओं ने अस्पृश्य हिन्दुओं को अपने कुएं से पानी नहीं भरने दिया और उनको गन्दे कुएं से पानी भरना पड़ा । उसका परिणाम यह हुआ कि तीन-चार दिन के अन्दर 16 आदमी अछूतों के जान से मारे गए । इस तरह से जुल्म आज भी हो रहा है । एक-आध आदमी हमारा मर गया हो तो कितना बलवा होता है और इतने बेचारे वे मरते हैं, यहां कालिंग अटेंशन आता है, भाषण हो जाते हैं, मामला खत्म हो जाता है । ऐसे यह सवाल मिटने वाला नहीं है और यह देश इस तरह से आगे नहीं जायगा । इस देश की प्रगति में जो यह बाधा है इस को अगर तोड़ना है तो आपको भरसक प्रयत्न करना चाहिए । मैं मानता हूं जैसे कई मेम्बरों ने कहा हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहती हैं कि अस्पृश्यता हमारे देश से हट जानी चाहिए । वह बहुत कोशिश कर रही हैं, जहां-जहां जायेंगी वह जी तोड़ कर बोलती हैं, भाषण करती हैं, हमको मालूम है कि बहुत कुछ लगन उनके दिल में है । लेकिन किसी व्यक्ति में कितना भी भारी लगन होने से यह सवाल छूटने वाला नहीं है ।

मैं आपको यह भी बताता हूं कि हमारे यहां की जो मशीनरी है वह बराबर इस काम में जो श्रेष्ठ हिन्दू लोग हैं बाधा डालते हैं, वह काम नहीं होने देते । अमल में नहीं लाते । हमारे इस विभाग के जो कमिश्नर हैं वह बहुत अच्छा काम करने वाले हैं । मैं उनकी क्या तारीफ करूं । खुद बूंटासिंह जी जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी के चयरमैन थे उन्होंने उनकी पूरी-पूरी प्रशंसा की है । शैड्यूल्ड कास्ट के जो बिहार के राज्यपाल हैं श्री भण्डारे, उन्होंने भी उनकी स्तुति की है । लेकिन उनके पास साधन नहीं हैं, स्टाफ नहीं है । इतना ही नहीं असिस्टेंट कमिश्नर जो उनके थे उनकी पोस्ट अबोलिश कर दी गई और अकल कमिश्नर सारे हिन्दुस्तान भर में अछूतों और आदिवासियों का काम करें, यह असंभव बात है । अगर सही माने में यह काम करना हो तो हमारे मिर्धा साहब यहां बैठे हुए हैं, हम जानते हैं कि उनके दिल में बहुत कुछ इस काम की लगन है, वह इसमें सुधार करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि उनके मंत्रालय की सद्भावना से यह काम होने वाला नहीं है । ठोस दृष्टि से हमें उनकी संख्या मुकर्रर करनी चाहिए कि इतने चीफ मिनिस्टर होंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन की जगहों में इतने लोग होंगे, उनके लिए जो जगहें रखी हैं सर्विसेज में वह खाली

[श्री पंढरीनाथ सीतारामजी पाटिल]

कागजों पर नहीं वह उन्होंने लोगों को देनी चाहिए। आल इन्डिया या प्रविंशियल सर्विस में जो 15 प्रतिशत की जगहें हैं उनके लिए उन्हीं में कंपीटिशन ेना चा हए। सर्वसाधारण लोगों के कंडीडेटों में खड़े रहेंगे तो वह मैरिट में नहीं आयेंगे, क्योंकि वह हजारों साल से पिछड़े हुए हैं, वह आई० ए० स० ेर आई० पी० एस० कब बनेंगे? उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। उनको देहातों में काम धंधों के लिए, ग्रामोद्योगों के लिए पूरा पैसा उनको देना चाहिए और गृहोद्योग शुरू करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय) : अब समाप्त कीजिए।

श्री पंढरीनाथ सीतारामजी पाटिल : आधा मिनट में खत्म करता हूं।

इतना हम करेंगे तो उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधरेगी और हमारे देश में गरीबी हटानी है तो सबसे पहले अछूतों की गरीबी और आदिवासियों की गरीबी हटानी पड़ेगी। उस गरीबी को हटाने से ही इस देश में समाजवाद आने वाला है और समाजवाद लाना है तो चलो अछूतों की बस्तियों में। इनको उठाने से हमारा देश उठेगा। इससे हमारा देश तरक्की करेगा. हमारे देश में समाजवाद आयेगा।

SHRI UMASHANKAR JOSHI (Nominated) : Madam Vice-Chairman, the Commissioner is neither himself, nor keeps us, under any illusion. He candidly tells us that villages in Mysore which gol prizes for anti-untouchability turned oul to be villages where untouchability was practised. The Report says that in the yeai 1970-71 in Gujarat prosecution under th« Untouchability Act was launched only ir 94 villages out of 18,428. This also perhaps should be taken with a pinch of salt looking to what happened on the 2nd ol October this year. On the very day ol Mahatma Gandhi's birth, in the capital of Gujarat which is proudly adorned witl his name, at a pooja function some inci dent took place and it is alleged that or the 3rd, the following day, Harijans wen belaboured by Government employees. W< are told that a police inquiry has beer instituted. So, one would like to wait foi the results of the inquiry.

Meanwhile, may I refer to what Shri Dalpat Shrimali, who is from the Sabarmati Ashram and has a Ph.D. degree has to say in "Garud" a magazine which he edits ? Two points deserve the attention of the Home Ministry. He says that the police station in the vicinity of the place where the pooja festival was taking place was locked on the 3rd. Perhaps the 2nd was a holiday, a public holiday, because of the birthday of the Father of the Nation. But the 3rd should not have been a field day for certain bad elements. The other point which he refers to, amongst several others, is that the Legislature was in session and Harijan Members were in town but it is alleged that they did not move even their little finger. I leave this sorry case at that with the hope that at a proper time the Ministry will get interested and look into such events.

As an educationist I have seen, at least in the universities of western India, young boys, 7 boys of 17-18 years of age, raising their voice against reservations for Scheduled Tribe and Scheduled Caste students in the medical colleges. People like me would like to plead with them that we have done injustice to them through the ages and where is the harm if they get a little weightage for admission. They are adamant. They say, this should not be there. One is shocked at seeing this cynicism at the age of 17.

Another source of tension in educational institutions is the occasion when a student has married or is about to marry an upper caste girl. On such an occasion there, is a good deal of tension and it ii very difficult for the Harijan students to protect themselves. Such situations are fraught with the possibilities of violence and they explode off and on in the campuses.

I have read the suggestions and recommendations about the Tribal Development Blocks. I do not know why the expenditure on the Tribal Development Blocks was slashed to less than one-half in Assam. Meghalaya was provided for but even then it fell from Rs. 73.5 lakhs to a meagre Rs. 30 lakhs in 1970-71.

There was also a slashing down in the expenditure in Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh and other regions. Nagaland, which had in the previous year only 13 lakhs got 23 lakhs in 1970-71 and rightly so.

In Gujarat the community development schemes had proposed to spend 20 per cent after roads and the actual performance shows that only 7.60 per cent was spent after roads. Of course, the remaining money was reallocated and used in another manner. But Gujarat happens to be hemmed in on one side with long hill ranges and in a backward region like Dharampur in Bulsar district, the whole tribal population is cut off from the rest when the monsoon is on. On the otherside of Dharampur we have very good roads leading to the neighbouring State of Maharashtra. I hope the last year's drought has inspired the powers that be to do something in the matter as early as possible.

The Scheduled Tribes are referred to in our languages as Adivasis or Adimjati. If that is so, they should be the inheritors of India. And they are mostly landless. We heard from the Home Minister about the possibility of their getting precedence over others in getting some pieces of land. The Report tells us that there are 17.4 million hectares of cultivable waste land in our country and the Government has been able to get a mere one million hectares under possession,. I think there should be a drive and this cultivable waste land should be passed on to the landless as early as possible.

It is said, the first will be the last and the last will be the first. But when? The Father of the Nation suggested that the highest post in the land should go to the so-called lowest. It has not happened. In this House there is no reservation of seats for the Scheduled Castes and Tribes, but some day we might have a Chairman from among them. At least either of the two high posts should go to the so-called lowliest.

If the officers refuse to accept water at the hands of Harijans, the Ministers can set an example. Gandhiji loved to go and live with Harijans. In my part of the country in the mid-fifteenth century, the high-casts Brahmin poet-saint Narsinh Mehta, on an invitation, went to the Harijans and when the Brahimns mocked at him, he said in reply, which in Hindi would be something like |JT rrfl, fT frg ft* ^tfTf !?n|S I' TO Let the Ministers, when they arrive on the scene, go and ask for water from the Harijan houses. But they are surrounded by vested interests, members of the Establishment, sycophants and what not.

Can we not do something in the matter? Reference was made to the caste system and it was said that the caste system was fastcrumbling. It appears that it is far away from disappearing from the national life. Lord Buddha ushered in a revolution in favour of the lowliest. One of his outstanding disciples was a sudra, but his revolution failed and the Establishment gol the upper hand. After the advent of Islam a stupendous wave of bhakti overran this country and again there were hopes foi the lowly people. Some of them rank among the greatest sons and daughters oi this country but again that revolution failed and the Establishment won, the caste-system became more rigid. After our coming into contact with the West, libertarian and egalitarian ideas came here and we thought that a brighter day, a day of hope for those who are the outcastes was round the cor ner. But what a cruel irony of fate tha after oui becoming an independent natioi our very democratic institutions have givei a new lease of life to casteism! The un touchables and the Scheduled Tribes an a big chunk and they have a weight in thi political life of the country. The Prim Minister, he or she, whoever it may be has to take note of this fact that they hav an immense political weight and the irony i that they are nowhere in the life of tb country. Their political importance is nc matched by their socio-economic uplift.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Please finish now, Mr. Joshi.

SHRI UMASHANKER JOSHI : Last word, Madam. If this revolution in favour of the lowliest fails for the third time in Indian history, we will be nowhere as a people. Gradually we have suffered a spiritual erosion, but this failure may mean our undoing.

Thank you.

SHRI SARDAR AMJAD ALI (West Bengal) : Madam Vice-Chairman, it is rather a great pleasure for me to take part in this debate with regard to this Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I was very attentively listening to the intervention made by the Leader of this House, the hon. the Home Minister and rather it will be a betrayal of my conscience if I do not unfold the thinking that took place within me. At that particular moment I was recalling a few lines of the great revolutionary poet Nazrul Islam. The incident was as follows.

A grand feast was going on in a mosque. All the mullahs and maulanas of the locality had assmbled there and at that particular moment or rejoicing one untouchable entered that mosque and prayed for alms. The mullah, the leader of the feast, said, you untouchable, you get out. Why, asked the untouchable. Did you pray, do you pray, do you call your God, he was asked. The untouchable said, no, and the reaction of the mullah was that not only that he should get out but he won't get any food and it is better that he does not get any food. That untouchable came out and said in very beautiful four lines of Poet Nazrul Islam :

आशीटा बछोर केटे गेधे मोर डाकिनी तोमाय कभू
तबु तो आमार खूदार अन्न केड़े नाउनिको प्रभू
कोथा कालापहाड़
मसजिद आर मन्दिर जतो भेंगे करो चुरमार

I have passed my eighty years of age and I have never called, never approached, Oh, my creator, Oh, my Lord, never for a moment did you allow that I would not get food. Therefore, at this particular moment when these Mullahs and these institutions refuse to give me any food, because I do not pray, because I do not surrender to you, my creator, I invite Kala Pahad : You demolish all these institutions from where touchability and untouchability is being practised. 1 am sorry to reiterate this sentiment of mine in this august House only to react to the speech which has been made at the time of intervention by a great leader of this country, the hon. Leader of the House and the great Home Minister of this country. It is lip sympathy which he simply unfolded in this august House. Certain goodwill was expressed in very good, beautifully coined and chosen words, but the fact remains that people of those communities, people of this great country are still being subjected to many atrocities and by whom? By our own people. It is a great misfortune for this country and for all Indians that though we have come out successfully from the British domination and exploitation and atrocities caused by those who invaded us, it is really an irony of fate for this nation to witness that even after 25 years of our achieving freedom. We, Members of Parliament, here debate and take part in crying hoarse that some people of our own country will have to be saved and will have to be given protection from the atrocities which are being inflicated upon them by another group of people of this country, I think the Home Minister of the country was listening to certain very passionate and pathetic instances that were being referred to by my hon. colleagues here. One instance was given mv my hon. friend, Mr. Goray. Another instance was given by Mr. Patil. I thought that at least the Home Minister of the country in this august House, after 25 years will act like a Kala Pahad and give a call to the entire nation and to the countrymen to stand side by side and put an end to all these atrocities. I am sorry to say that I did not find some such reaction. It may be that some wise Member of this House will put me to criticism only because being a youngman I put my reaction in this way. I find that these atrocities are going on. Even when we are consider-

ing the Report of the Commissioner and two or three days earlier I read in the Times of India that the same atrocities have been committed in some parts of Gujarai. The reply of the Gujarat Chief Minister in the Legislative Assembly, Mr. Chimanbhai, was only two persons were arrested, and that the police was investigating into the affairs. How long will you investigate these matters ? I do not know whether these uptouchables, who are still being subjected to this sort of vandalism by the so-called touchables or by the so-called upper class of society, will definitely veer round, in order to give a call for emancipation from these kinds of atrocities.

Madam Vice-Chairman, in this Report I find that certain very valuable suggestions have been made by the Commissioner in Chapter 2. Chapter 2 discusses the educational development of this community. First of all, I must sharply react to the use of the word 'community' even after 25 years, the fact remains that I have to use it. I would have been much more glad if I were not to use it. In Chapter 2 dealing with the educational development of these communities, a very beautiful picture has been painted. Of course, there is a certain betterment in regard to the educational aspect of this community.

The picture has been very nicely narrated here. It has been referred by the hon*ble Home Minister here that in the field of education of these backward classes there is definitely upliftment But the report shows that the upliftment is only in the air.

With regard to enrolment in the middle and secondary schools the data shows a sharp decrease. Why is that so ? In my humble submission to the Home Minister particularly, this sharp decrease is because they are not in a position to pay for their education in the middle and secondary schools because they are not financially sound. Therefore, not only that we should be very much satisfied with this report, side by side we have take into account the economic and the financial aspect of these hrothren of ours and judge whether they can take higher education in highei and middle classes,.

The Commissioner has very rightly mentioned here about the quantum ol scholarship and certain incentives. The progress may look satisfactory but in my humble opinion it has to be increasec much more so that the scourge of the age old institution, this institution of casteisn dies out at a much more faster speed otherwise the danger which might arise one day cannot simply be avoided.

Madam, in the report the learned Com missioner has shown the figures ol admissions in Engineering and Medica colleges. You will be surprised to noti that after 25 years, although the Govern ment has announced that there should t* certain reserved seats in the Medica colleges, the report of the Learned Com missioner shows that there are seventeej Medical colleges in the country in whicl there is no such reservation. In certai Medical colleges though there are reserv ations, actually the reserved seats do no go to them. Sir, in the capital city o Delhi in the Maulana Azad Medical Collegi you find that some people in the name o being Scheduled Castes and Schedulei tribes have got admission.

Therefore, if the Home Minister say that a very strong attitude and very stron; steps are being taken, I am sorry I cannc accede to his arguments, I am sorry cannot accept that strong steps have beei taken in this regard. {Time-bell rings Madam, I will finish. In the engineerin colleges also, the same thing is going or In this connection, I must submit that th Commissioner has pointed out that wit regard to admission in the medical an engineering colleges, different medics colleges and different engineering college are adopting different types of eligibilit for the Scheduled Caste and Schedule Tribe students. In some colleges, if is 5 per cent; in some colleges it is 45 per cen There is no uniformity of percentage t marks all over the country. This shoul be brought about immediately That my submission.

[Shri Sardar Amjad Ali]

With regard to the service conditions, many things have been said here. I will simply draw your attention to page 18 of the report. There the Commissioner has mentioned the backlog in the services in regard to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Although we say that there is a gradual improvement on this score, you will be surprised to find that on page 18 of the Report, the Commissioner has reported that in Class I there is a shortfall of 1,812 in regard to the Scheduled Castes and 850 in regard to the Scheduled Tribes. In Class II, the figures are 1,891 for the Scheduled Castes and 1,145 for the Scheduled Tribes. In Class III, the figures are 1,440 for the Scheduled Castes and 21,604 for the Scheduled Tribes. May I ask the hon. Home Minister why it is so? Is there any paucity of these people to be given employment in these particular cadres? I believe that it is not the actual picture. The actual picture is that people who are occupying the top positions in these offices and who can deliver the goods to these reserved communities, are very touchy and I should say, they are not even prepared psychologically to make any room for these under-privileged classes. Therefore, when the Home Minister says that they are taking steps, may I ask the Home Minister to make a probe into this matter as to who are the officers who do not give these opportunities to those to whom these opportunities ought to have been given in these particular services? (.Time-bell rings) Just a minute, Madam. Therefore, this deficit which is increasing at a fast rate should be removed immediately. That is why I say that mere lip-sympathy and sympathy expressed in well-chosen and fine words will not do. In this country I apprehend that you will be inviting not one Kala Pahar but many Kala Paharv

Now, with regard to funds for the development and welfare of these depressed classes, what is the attitude? The total Plan allocation is very meagre, I should submit. I have got statistics with me. The only plausible reason that is being given by the Government is that because of paucity of funds, they cannot allocate more funds for the welfare of these depressed classes. Is that the real position? I believe it is not the real position. You have to consider the colossal magnitude of the problem : 21.52 per cent of the entire population of the country belong to these depressed classes. If paucity of funds can be taken as a good reason for not allocating adequate funds for the welfare of these particular classes, then it would be taken as a very good reason for others, too. But unfortunately that is not so.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Please finish now.

SHRI SARDAR AMJAD ALI : Madam, just one or two minutes more. Regarding the Untouchability Offences Act, every day here in this House we clamour that in some part of the country or the other a certain thing is going on. The Untouchability Offences Act is there. I had made a suggestion in the Select Committee, when the Criminal Procedure Code was being amended, that the Untouchability Offences Act should be brought under the Schedule so that any person committing the same offence under the Untouchability Offences Act will be treated as a habitual offender. In the Select Committee, the suggestion was accepted, but unfortunately when the Bill was presented, the suggestion was completely omitted. I do not know why it was done.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) •. Please sit down now.

SHRI SARDAR AMJAD ALI : Just a second. When the Home Ministry says that it is the social consciousness that will have to be roused to stop these untouchability offences, may I suggest that in order to rouse the civic sense of the population, it is high time that we imposed a punitive tax upon all the people residing in the locality where an atrocity is committed upon the Harijans? Probably it is high time that we did so. I hope that these ghastly things, perpetrated upon our

brothers by our own people, will be looked into with much more seriousness by our Home Minister lest we should invite more calamities all over the country. Thank you. 5 P.M.

श्री महाबीर दास (बिहार) : महोदया, आज जब देश में हरिजनों के प्रति अपने भाषण में सब रोना रो रहे हैं तो मुझे एक और रोना रोना पड़ा कि कांग्रेस की तरफ का एक भी प्रतिनिधि हम लोगों का रोना सुनने के लिए नहीं बैठा है। इस रोने के साथ एक रोना हमने जोड़ दिया। आलोचना करने के लिए बहुत हो सकते हैं, लेकिन हृदय से महसूस करने के लिए कितने हैं यह महसूस करने का समय आज हमको था और मैंने पाया।

मैं अभी अपने माननीय साथी को सुन रहा था कि हमारी सर्विसेज में कितनी कमी हुई है। एक तो समूचे राज्य सरकारों की गिनती है, परन्तु जब से हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने संभाला है, जब से मैं देख रहा हूं कि क्रमशः केन्द्रीय कर्मचारियों में वृद्धि होती रही है और यह वृद्धि अपेंडिक्स 8 में देखें तो क्लास 1 आफिसर्स में 1968 में 2.08, 1969 में 2.29, 1970 में 2.34 और 1971 में 2.70 था। यह प्रतिशत शो करता है कि इस किस्म से बढ़ोत्तरी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में हरिजनों की होती रही हैं। यही द्वितीय, तृतीय श्रेणियों में भी हुई है। चतुर्थ श्रेणी में तो कम हुए हैं। जब कि पहले 18.09 परसेंट था तो 1971 में 17.72 परसेंट हो गया। ये सारी बातें मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार जितनी जागरुक है और जितना वह ध्यान दे रही है, अगर उतना ही हमारी राज्य सरकारें काम करने लगें, ध्यान देने लगें तो हम समझते हैं कि जो रोना रोया जा रहा है उसमें कमी हो सकती है।

1967 से 1969 तक में आप देखें कि 1,112 हत्यायें की गई हैं। उसके बाद की फिगर्स और भी हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि ये हत्यायें जो होती हैं यह जागृति की निशानी है। हत्या तभी की जाती है जब हरिजनों में यह ताकत हुई होगी कि वह मुकाबला करें। यही जागृति की निशानी हैं। मैं समझता हूं कि जिस कौम में मरने की शक्ति नहीं है वह जिन्दा रह नहीं सकती। मैं उसका रोना इसलिए नहीं रोता कि मैं चाहता हूं कि आज हरिजनों में ताकत हो, वह मर मिटने के लिए तैयार हों, उनमें शक्ति हो। तभी यह सामाजिक दुर्गुण दूर हो सकता है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 300 लाख रुपये रखे गये थे, परन्तु उसका कुल खर्च कितना हुआ 162.04 लाख। मैं बहुत अदब के साथ इस हाउस के द्वारा अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचवर्षीय योजनाओं में जितना वह रख सकते हैं रखें, लेकिन चतुर्थ योजना में जितनी कमी हुई है उस रुपये को भी दें ताकि आपका गृह मंत्रालय इस काम को पूरा कर सके जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अधुरा रह गया था।

अब आप देखेंगे कि मेडिकल कालेज में और अभी हमारे माननीय साथी ने कहा कि इंजीनियरिंग कालेज के लिए भी सुरक्षित स्थान किये गये हैं। लेकिन सुरक्षित स्थान तो हुए हैं पर उनमें कितने लोग आये हैं यह आपको देखने से पता लगेगा कि कितना परसेंटेज देना चाहिए वह कभी नहीं हुआ। यहां तक कि आप देखेंगे कि अगर 481 का एडमीशन हुआ है तो उस में कुल दो हरिजनों को एडमीशन मिला है जब कि प्रतिशत उनका दस या पांच का रखा गया है। तो अगर 484 में बीस भी हों तो बात समझ में आती हैं, लेकिन वहां कुल दो हरिजन लिये गये। यह सुझाव ठीक है कि अगर आप उनके लिए 45 या 50 या 60 प्रतिशत नम्बरों की बात रखते हैं तो उसके लिए गृह मंत्रालय हर यूनिवर्सिटी को यह आदेश दे कि वह हरिजनों के लिए एक समान नम्बरों का प्रतिशत निश्चित करें और हरिजनों के बीच में जो अधिक नम्बर उस प्रतिशत में ले आये उनको भर्ती किया जाये, तभी इंजीनियरिंग कालेजों और मेडिकल कालेजों में हरिजनों के लड़के आ सकते हैं।

मैं भारत सरकार को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि 5 हरिजन और चार आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा गया है। इसी तरह से यदि हरिजन और आदिवासी छात्रों को हर साल भेजा जाय तो वह उत्तम है। नहीं तो 1970-71 की रिपोर्ट के लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और अगर वह 1971-72 में कम हो गया हो तो ठीक नहीं होगा और 1972-73 में तो उसमें वृद्धि ही होनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

[श्री महावीर दास]

एक बात की ओर मैं और आप का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वह बात है रिसर्च की। हमारे तमिल नाडु के दोस्त बहुत बोल रहे थे, लेकिन रिसर्च से पता लगा है कि श्री पुष्पम् कालेज, पूंडी के प्लानिंग फोरम के द्वारा तमिल नाडु राज्य के तंजबुर जिले के तिहवयुर प्रखण्ड में किये गये सर्वेक्षण से भी पता चला है कि होटलों, चाय की दुकानों, मंदिरों तथा नाइयों की दुकानों में अब भी छुआछूत बरती जाती है। तो मैं तमिल नाडु का ध्यान खास तौर पर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां उनके अत्याचार की बड़ी-बड़ी कहानियां हैं। वहां की सरकार का ध्यान उस ओर जाना चाहिए ताकि वहां के हरिजनों पर जो यह अत्याचार हो रहा है, वह कम हो।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक जगह हमारे कमिश्नर ने टिप्पणी की है। (*Time bell rings*) मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं। मेरा निवेदन है कि हमारे 58 केन्द्रीय विद्यालय हैं और उनमें 688 छात्र हरिजनों के हैं, कुल प्रथम श्रेणी से लेकर उच्च क्लासेज तक तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम केन्द्रीय विद्यालयों में तो हरिजनों के प्रवेश के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं हरिजन कल्याण कार्य को प्रगतिशील बनाने के लिए गृह मंत्रालय को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि दीक्षित जी ने आज जो भावना व्यक्त की है वह बड़ी सराहनीय है। हमारे श्री मिर्धा जी और श्री मोहसिन साहब की भावनाओं में भी जो मैंने पाया है उससे मेरा विश्वास बढ़ा है कि गृह मंत्रालय अवश्य ही बहुत कम समय में हरिजनों के दुख को दूर करने की कोशिश करेगा। कमिश्नर के जो सुझाव पृष्ठ 3 पर दिये गये हैं उनके संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और अगर उनके सुझाव कार्यान्वित किये जा सकें तो उत्तम होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी जो सरकार बनी है और इससे पहिले जो सरकार थी उसमें मैं यह अपने विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि, हरिजनों को मंत्री परिषद् में काफी स्थान मिला है और हम लोग उससे संतुष्ट हैं और इसलिए संतुष्ट हैं कि वहां एक ही जाति को नहीं लिया गया है, अन्य जातियों को भी लिया गया है और एक बाल्मिकि को भी ले कर वह मंत्रि परिषद् बनायी गयी है। इसलिये मेरा विश्वास जमा है कि अब हरिजनों का उद्धार हो सकेगा।

श्रीमन्, यद्यपि हमारे माननीय मिर्धा साहब ने यह कहा है कि छात्रवृत्तियों की रकम को बढ़ाया है, उसमें वृद्धि की गई है, लेकिन मैं कहूंगा कि जब प्लानिंग में बहुत कम रुपया रखते हैं तो फिर कैसे होगा, प्लानिंग में रुपया नहीं बढ़वा सकेंगे तो वास्तव में जो चाहेंगे वह पूरा नहीं हो सकेगा। मैं कहता हूं कि युद्ध स्तर पर काम करने के लिये प्लानिंग कमिशन को सब से ज्यादा रुपया कल्याण विभाग को देना चाहिये ताकि कल्याण का काम हो सके। अगर कल्याण का काम नहीं होगा तो फिर कहां काम होगा। मेरा निवेदन है कि प्लानिंग कमीशन और हमारा गृह मंत्रालय दोनों जितना हो सके उतना झगड़े और अगर हो सके तो इस चीज को हमारे सदन के सामने रखें, संपूर्ण सदन आपका साथ देगा कि कल्याण के लिये अधिक से अधिक रुपया देना चाहिये ताकि कल्याण का काम पूरे तरीके से किया जा सके।

धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Yes, Mr. Shyam Lai Yadav. Not here. Yes, Shrimati Shushila Shankar Adivarekar.

SHRIMATI SUSHILA SHANKAR ADIVAREKAR (Maharashtra) : Madam Vice-Chairman, while going through the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and listening to the discussions, it seems that it is very rarely that any new proposal cornea up during the discussions in Parliament. The same old grievances are aired and the same old remedies are proposed and suggested year after year. The crux of the problem is not that there has been no progress in the conditions of the backward classes. But whatever progress there is so far has beers entirely lopsided. These days the problems of the Harijans are going like communal virus mainly because we have now placed a new emphasis on the Minimum Needs Programme, better agricultural production and land reform legis-

lation and so on. But, unfortunately, the emphasis on these programmes not being even, a very peculiar situation has arisen to exploit the backward people, the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes with the disastrous results like the Harijan murders, assaults, raping of wom-men, burning of houses, etc., which have increased beyond proportion. I need not repeat the grim picture of the disabilities under which the Harijans continue to live even today. They are denied the most elementary amenities of life such as access to the village well and such others, while, on the other end of the scale are the columns full of statistic figures showing how many backward communities have secured jobs in the Government service, showing how many people secured scholarships and how many secured employment in various fields and so on. There is obviously something wrong with the pattern of assistance which, instead of relieving their hardships where &sy acutely exist, helps in contributing more to widen the social and economic disabilities amongst the backward communities. In many remote and rural parts of the country they continue to suffer from many indignities

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

that make a mockery of the law of the land. It is not as if nothing has been done in this field during the last 25 years or so. But very much more remains to be done which requires a speedy approach to this deep-rooted social evil and it has to be taken up by all of us. The Central Government just leaving it to the States and the States in turn leaving it to the districts which are less concerned with this problem will not solve this issue. The Centre has to take the initiative and impress upon the States to be more sincere in following it up. All educational programmes are the real corrective measures. But they have a remarkable slow speed to achieve the desired results and sometimes these educational programmes, after raising the expectations, bring the frustration when they find no place in the society and so they are apt to be more ungenerous towards the backward people with the result that we find more of apathy on their part towards the education resulting in children's dropping out from schools and less literacy amongst the adults. Measures to correct these are more important than anything else. The recommendations in the Report under the present conditions are very important and are to be implemented so as to ensure that the benefits of all the proposed development programmes reach the weaker sections of society with special efforts to bring them to the level of others.

Another thing that we require to do besides the speedy implementation Sir, if we have to implement these measures, is the firmness to deal with all the overt practices of untouchability and have more stringent penal provisioas. More social welfare and youth organizations should be involved to work for the better education and social upliftment programme, by providing extra impetus, by way of financial aids, in full, without any reductions, and more housing facilities to the social workers and for their activities. Special programmes for educating the women should be undertaken. It is the work at the grass root level which will help us more to achieve our objectives.

One more point, Sir, is that the Commissioner should have more powers and functions to play a more regular and active role in trying to expedite the programmes. He should take adequate measures to percolate all the programmes and all the information down to the beneficiary level. The very fact that more than one-fifth of our total population continues to suffer human indignities and economic inequalities is a very sad affair in our work in our outlook, in our planning and ID our sincerity to our approach to the problem to improve the conditions of those unfortunate ones.

The Report deals with various suggestions and recommendations on almost all the aspects which can help to improve the conditions of Scheduled Castes and Sche-

[Shrimati Sushila Shankar Adivarekar]

duled Tribes. Let us hope that this Report will at least make the Government take right steps in the right direction to expedite these programmes and make a proper evaluation of the following actions.

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार): उपसभापति महोदय, यह हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशनर की बीसवीं रिपोर्ट पर ग्राज इस सदन में चर्चा हो रही है। इससे एक बात स्पष्ट जाहिर है कि इससे पहले 19 रिपोर्टें लिखी जा चुकी हैं ग्रौर उनके ऊपर सदन में बराबर चर्चा भी हो चुकी कि क्या करना चाहिये। इसकी बड़ी सुंदर-सुंदर योजनायें ग्राईं। लेकिन सवाल यह है कि ग्राज जो कुछ भी, इस रिपोर्ट में भी ग्रौर इसके पहले की रिपोर्ट में भी जो चर्चा थी, सवाल इतने पर है कि हमने जो भी टार्गेट्स फिक्स किये, हमने ग्रपनी योजनाग्रों में नौकरी के लिये या दूसरे प्रकार से उनकी प्रगति के लिये, उनकी हर तरफ की तरक्की के लिये जो कुछ भी रखा, जो कुछ स्टेट्स को दिया, प्लान टार्गेट्स बनाये, क्या हम उस तक पहुंचे हैं, सवाल उस पर लटका हुग्रा है कि वे हमारे टार्गेट्स एचीव हुए कि नहीं, ग्रौर ग्रगर नहीं हुए तो क्या कारण है उसका? यह ठीक है कि हमने हाउसिंग स्कीम्स भी बनाईं शहर के लिये भी ग्रौर गांवों के लिये भी, हमने उनकी पढ़ाई के लिये भी पैसा एलोकेट किया, उनकी नौकरी के लिये रिजर्वेशन्स किये, उनकी हर तरह की सुख ग्रौर सुविधा के लिये हमने कहा कि ये-ये बातें होनी चाहियें। ग्रनटचेबिलिटी हटाने के लिये, छुग्राछूत की बात हटाने के लिये हमने कहा सरकार ये-ये काम करेगी। जमीन के बंटवारे के लिये हम ने कहा कि हम सीलिंग करके जमीन जो कुछ भी बाकी उपलब्ध करते हैं, उसको हरिजनों में बांटेंगे ग्रौर उस भूमि को ग्राबाद करने के लिये हम उनको सभी सुविधायें देंगे, गांवों में घर बनाने के लिये 800 रु० तक भी हम देंगे, पास (Home stead land) की जो जमीन होगी उसका दाखिल खारिज कर देंगे। इस प्रकार करने को तो हमने कुछ बाकी नहीं रखा है। हमने सारी योजनायें बना लीं, हमने सारे ग्रधिकार उनके लिये स्वीकृत किये हैं सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी जो गांधी जी का स्वप्न था ग्राजादी के पहले कि भारत में हरिजनों का सुंदर संसार बनेगा, उनको भी कास्ट हिन्दूज के बराबर के ग्रधिकार प्राप्त होंगे, उनके साथ रहने-सहने की उठने-बैठने की हर प्रकार की सुविधायें उनके बच्चों को मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी, ये सब हम क्या कर पाये हैं? ग्रौर ग्रगर नहीं कर पाये हैं तो क्यों नहीं कर पाये हैं? ग्राज भी मैं गांवों में जाती हूं तो देखती क्या हूं? क्या कास्ट हिन्दूज के मौहल्ले के बीच उनके घर बने हुए हैं, क्या उनके कुंग्रों का पानी उतना ही साफ है जिस तरह से कास्ट हिन्दूज के कुंग्रों का पानी साफ है? क्या ग्राज हम कह सकते हैं कि उनके कुएं का पानी हरा नहीं है? जिसको पी कर उनकी ग्रांतों में तड़पन हो जाती है, उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। ग्रौर यह हालत जहां की तहां मौजूद है। लेकिन इन सब बातों को कहने का कोई फायदा नहीं। इन बातों को मैं इसलिये नहीं रख रही हूं सरकार के सामने कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती, बल्कि इसलिये कि मैं जानती हूं ग्रगर सरकार के ग्रन्दर बेचैनी नहीं होती, ग्रगर स्वयं प्रधान मंत्री के ग्रन्दर ग्रौर दूसरे मंत्री-गण के ग्रन्दर यह बेचैनी नहीं होती कि हम उनको उनके सारे ग्रधिकार ग्रौर सारी सुख-सुविधायें दे सकें ग्रौर हम उनको, कांस्टीट्यूशन के प्रीएम्बल में जो कुछ कहा है उन सारी बातों को हम पूरा कर सकें, तो मैं यह बात सरकार के सामने नहीं रखती।

मैं यह बात इसलिये रख रही हूं कि इस तरह के लूपहोल्स क्यों हैं कि हम इस चीज को नहीं कर पाये? इसके दो, तीन कारण हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत ग्रच्छे सुंदर जो विचार रहे हैं, जो टार्गेट थे, जो कुछ करना चाहते थे, उसमें हमको एचीवमेंट नहीं मिल सके यानि उसकी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके।

इलाहाबाद के ट्रेनिंग कालेज ग्रौर स्कूल की चर्चा इस रिपोर्ट में है ग्रौर इस रिपोर्ट में लिखा है कि सिर्फ 6 ग्राई० ए० एस० ग्रौर ग्राई०पी०एस० ने पास किया है; क्योंकि वहां पर बहुत सी खामियां हैं। सवाल यह नहीं है कि उस इंस्टीट्यूशन में चार

टीचर बदल दिये जायें, उस इंस्टीट्यूशन के लिये मकान बना दिया जाये । दो घर जोड़ देने से बात नहीं होगी । हम को तो एक दम रूट काज पर जाना होगा कि कहां पर लूपहोल्स हैं, कहां पर दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हम अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ।

हमने इस बात को देखा कि महान नेता विनोबा जी का भी जो भूमिदान का मकसद था, उसको हम पूरा नहीं कर सके । कागज पर ब्लाक्स भूमिदान हो गये, डिस्ट्रिक्ट्स भूमिदान हो गये, पूरा प्रदेश भी भूमिदान हो गया, पर देखना यह है कि इससे हरिजनों को क्या मिला ? हरिजनों की हालत जिस तरह से पहिले थी वैसे ही आज भी है और जो जहां पर पहिले रहता था, आज भी वहीं पर रह रहा है । इन सबके पीछे क्या बात है ? इनके पीछे दो, तीन कारण हैं, जिनको मैं सोच पाई हूं । मैंने इस सम्बन्ध में कोई रिसर्च नहीं किया है, लेकिन गांवों में जाने पर और उनके दुःख दर्द की जो कहानी हम लोगों को सुनने को और देखने को मिली हैं, उससे जो कुछ मैं समझ पाई हूं, वह यह है कि दो तीन खामियां हैं, जिसकी वजह से यह दिक्कत हो रही है और जिसकी वजह से हरिजनों की हालत में सुधार नहीं हो रहा है।

एक बात तो यह है कि हरिजनों के पास सीलिंग की जो जमीन आई है, उसका जिस तरह से बंटवारा होना चाहिये था गांव में, वह ठीक तरह से नहीं हुआ । जिनको जमीन मिलनी चाहिये थी, उनको जमीन नहीं मिली और जिनको मिली, उनके पास पैसा नहीं था और वे कुछ नहीं कर सके । इसलिये जो भूमि बांटने का आर्गेनाइजेशन था, जिसको सरकार ने खड़ा किया था, उसमें सुधार की जरूरत है । मैं इन सुधारों में दो, तीन बातें जोड़ना चाहती हूं ।

यह जो गृहस्थ की जमीन आपको अधिक मिली है सिर्फ उसके बंटवारे से आपका काम चलने वाला नहीं है । सरकार के पास भी बहुत सी जमीन है। इसके अलावा एक और क्षेत्र है जो बिलकुल अछूता है, जिसको सरकार अगर चाहे तो टैप कर सकती है ताकि वहां से कुछ जमीन निकाली जा सके । अगर वह इस जमीन को निकाल सकती है तो इसको वह हरिजनों को दे सकती है और इससे उनको ज्यादा सुविधा हो जायेगी । मुझे इस सम्बन्ध में दूसरे प्रदेशों की स्थिति के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन बिहार के बारे में मुझे पता है कि प्रत्येक गांव में काफी जमीन ऐसी है जो पहिले के जमीदारों की थी और जिस को उन्होंने धार्मिक संस्थाओं के लिये दे दिया था । इस तरह की जो जमीन है वह दो हजार और चार हजार एकड़ तक की है । यह जमीन जमीदारों ने इस लिये दी थी ताकि उसकी आमदनी से मंदिरों की देखभाल होगी, वहां पर विद्यादान होगा और वहां पर जो गरीब अपाहिज लोग हैं, उनके लिये अस्पताल का प्रबन्ध हो सकेगा । और जमीन की जोत वहां की गरीब जनता करेगी। मन्दिर इत्यादि के खर्चे से जो बचेगा वह गरीब भूखे लोगों में बटेगा । आज क्या हो रहा है ? क्या जिन तीन चार मकसद के लिये जमीन दी गई थी, वह क्या पूरी हो रही हैं ? न तो मंदिरों की ही देखभाल होती है, न शिक्षा का ही कोई प्रबन्ध है और जो वहां पर गरीब लोग थे, जो पहिले जमीन जोतते थे बटाइदारी बिल पास होने से उन्हें मुश्किल से जमीन को जोतने दिया जाता है । मैं इस बारे में होम मिनिस्टर साहब को करीब पच्चीसों जगहों का उदाहरण दे सकती हूं, जिसके बारे में मेरी जानकारी है । जिस जमीन को पहिले से हरिजन जोत रहे थे उनको हटा कर, उन पर मुकदमा चलाया गया और इस तरह से 4—8 साल तक मुकदमा चलता रहा । उन बेचारों के अपने औरतों के जो कुछ भी दो चार चांदी के जेवर थे, कांसे और पीतल के बर्तन होते थे, सब हरिजनों ने एक जगह पर जमा करके उनका आक्सन करवाया और किसी तरह से उस जमीन को टिकाये हुए हैं तथा अपने बाल-बच्चों की परवरिश करते हैं । तो यह सब बातें हैं जिनकी तरफ मैं गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं, इनकी तरफ भी देखें । हम यही करते आये हैं कि जो ब्यौरा तैयार होता है, उसको पढ़ लेते हैं कि इतने लोगों का फायदा हुआ, इतने लोगों को नुकसान हुआ,

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

इस तरह की रिपोर्ट छाप देते हैं । आप जमीन लीजिये बड़े काश्तकारों से लीजिये, जमीदारों से लीजिये, लेकिन जो ये दो तरह की जमीनें हैं। उनके बारे में भी देखिये कि आप क्या कर सकते हैं? मैं नहीं मानती हूं कि ऐसा करने से धर्म की हानि होगी । कुछ लोग चाहे वे स्टेट में हों या केन्द्र में हों, कहते हैं कि इससे धर्म की भावना को ठेस लगेगी । मेरा इतना ही कहना है कि धर्म की भावना को ठेस नहीं लगेगी; क्योंकि जो एनडाउमेंट डीड्स हैं, वे मैंने भी पढ़े हैं, उनमें कहीं भी जिक्र नहीं है क यह खाली कास्ट हिन्दुओं के फायदे के लिये ही है । मन्दिर के अन्दर जायें या न जायें, इस बारे में बहुत जगह बहुत बहस है और उस बहस में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन जो चार हजार, पांच हजार, छः हजार बीघे जमीन है, उस जमीन को कास्ट हिन्दू जोते या शेड्यूल्ड कास्ट वाला जोते या शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जोते, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है । मैंने भी काफी एनडाउमेंट डीड्स पढ़े हैं ।

इसके अलावा जब तक हम हरिजनों की आर्थिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते । अभी जो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनकी स्त्रियां, पुरुष और बच्चे सब मिल कर प्रतिदिन जब तक मजदूरी न करें उनके पास अनाज नहीं होता । और इसलिये जो आप स्कूल खोल देते हैं या स्कूल्स में जो रिजर्वड सीट रख देते हैं वहां हरिजनों के बच्चे नहीं मिलते हैं, वे आते ही नहीं हैं; क्योंकि उसका मतलब होता है कि उनकी फैमिली इनकम में दो रुपये की कमी जो आज की महंगाई में वे एफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब तक आप उनको आर्थिक सुविधायें नहीं देते जैसे मिसाल के तौर पर गांव में जो छोटी सड़कें बनती हैं, उनका कान्ट्रैक्ट उनको भी दीजिये, छोटे-छोटे कलपुर्जों के बनाने के लाइसेंस उनको भी दीजिये और इस तरह की बहुत सी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो गांवों में और शहरों में आप बिठा रहे हैं, उनमें उनको भी मौका दीजिये ।

जो उनकी पढ़ाई का तरीका है उसमें फरबदल लाइये । अभी क्या हो रहा है ? जो पोलीटैक्निक्स हैं उनमें हरिजनों को जो पढ़ाया जाता है वे वही सड़ी-सड़ाई चीजें हैं जिनको व सीख कर बनाएं भी तो उनकी बाजार और दुकानों में खपत नहीं है । तो उनको उससे फायदा नहीं होता । इस तरह से जब तक उनकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी, तब तक उनके डेवल्पमेंट की कोई योजना कार्यान्वित नहीं होगी ।

उनके ऊपर जो ऋण है उसके कारण भी उनको बड़ी परेशानी है । उनके ऋण दो प्रकार के हैं, एक सरकार से लिये हुए ऋण हैं और दूसरे साहूकार से लिये हुए । जो सरकार की तरफ से से ऋण हैं उनको आप माफ कर सकते हैं, जसे बैड एक्सपेंडीचर को आप राइट-आफ करते हैं उसी तरफ से आप हरिजनों के ऋण को राइट-आफ करें और जहां तक साहूकार का सम्बन्ध है उनके लिये ऐसी सुविधा दीजिये कि ब्लाक में उनको आसानी से ऋण मिल सके । अभी जब वे बैंक्स में जाते हैं तो उनको इतने पेचीदा-पेचीदा फार्म भरने होते हैं कि उन फार्मम्स को भरना उनके लिये सम्भव नही है; क्योंकि उनके बच्चों में या उनके मर्दों में इतनी शिक्षा नहीं है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि उनकी जो स्त्रियां हैं. उनकी शिक्षा जब तक आप अधिक नहीं बढ़ायेंगे, इनसेन्टिव्स नहीं देंगे पढ़ने लिखने की तरफ, उनकी स्त्रियों के आर्गेनाइजेशन नहीं बनायेंगे गांव में कि ये स्त्रियां अधिक बच्चे फलाने स्कूल में डालें तो उनको कुछ विशेष सुविधा होगी । यह सब कुछ नहीं करेंगे तब तक उनकी जो प्रगति आप चाहते हैं, उनको जो अधिकार आप दिलाना चाहते हैं वह नहीं दिला सकते हैं; क्योंकि अधिकार लेने के लिये आत्म-विश्वास चाहिये । अभी उन बेचारों को यही समझ नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं कांस्टीट्यूशन के मुताबिक, सरकार हमें क्या अधिकार दे रही है, हम उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं । अभी आपने सुना कि मैडिकल कालेज में या दूसरी जगहों में आपने जो अधिकार दिये हैं, उनका भी वे बेचारे फायदा नहीं उठा पाते और दूसरे उनके नाम से फायदा उठा लेते हैं ।

अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें, उनकी प्रगति हो और उनको अपने अधिकारों की समझ हो तो उनके लिये शिक्षा, उनकी आर्थिक उन्नति और उनके लिये ऋण आदि इन तीन चीजों की जब तक आप व्यवस्था नहीं करते, तब तक आप हरिजनों की कोई भी तरक्की नहीं कर सकते या किसी तरह से उनको उस स्थिति की समानता में नहीं ला सकते, जिसमें दूसरे लोग हैं। यद्यपि पापुलेशन के आधार पर उनकी संख्या अधिक है, लेकिन हर चीज में, हर जगह पर वे हार जाते हैं। उनके मुकदमे होते हैं, जमीन के मुताल्लिक उनके पास रुपया नहीं होता कि वह मुकदमे ल सकें। सरकार जब तक उनको लीगल एडवाइस की सुविधा नहीं देती है, वह अपना जमीन के लिये अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो आपको देखनी हैं।

डिफेंस सर्विसेज में हरिजनों को भी लाइये। उनको वह ट्रेनिंग की सुविधा दीजिये जो दूसरों को आप दे रहे हैं, उनके लिये आप रिसर्च सेंटर बनाइये। खाली हरिजन कह देने से कुछ नहीं होता। हरिजनों में भी कई जातियों के लोग , कोई कर्मकार या व्यापार की तरफ जायेगा, किसी की बुद्धि तेज होती है, कोई लड़ाई में दक्ष है। तो किस जाति के लिये किस प्रकार का झुकाव है, रुचि है उसके लिये उस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिये।

आसाम में जो जातियां हैं उनमें से दो जातियों को आप ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट से बाहर छोड़ दिया है। संथाल और ओरांग। इनको भी आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में जोड़ दें। और भी बहुत सी जातियां हैं जिनको इस लिस्ट में आपने नहीं रखा है। उन लोगों को, जो सुविधायें और लोगों को मिलती हैं, वह सुविधायें नहीं मिलती हैं। उनको भी जोड़ कर वह सारी सुविधायें देने की कृपा करें।

श्री कमल नाथ झा (बिहार): डिप्टी चेयरमैन महोदय, मैं समझता हूं कि बातें तो जितनी महत्वपूर्ण हैं सभा में बतलाई जा चुकी हैं। मैं सिर्फ एक दो बातें कहना चाहता हूं

स्वराज्य के 25 वर्ष के बाद भी हरिजनों और गिरिजनों का कल्याण हो और उनका उत्थान हो, इस इंटेंशन में किन्हीं को संदेह नहीं है। लेकिन जितना प्रश्न इंटेंशन का है, उससे अधिक प्रश्न, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डाइरेक्शन का है। मंतव्य का जितना प्रश्न नहीं है उतना गंतव्य का प्रश्न है। बहुत सी बातें मैं सुन रहा था कि साहब नौकरी में रिजर्वेशन ज्यादा होना चाहिये। लेकिन जितना हमारा कार्य था उस सबको हम 25 वर्षों में पूरा कर लेते तो दो लाख और आदमियों को हम नौकरी देते। अब तक वह जरूरत के अनुसार दस लाख हरिजनों को सुख सुविधा मिल गई होती। लेकिन 12—15 करोड़ की जनता में अभी भी दो चार लाख लोग जो आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, एम०एल०ए० या एम० पी० या मिनिस्टर हैं वह लोग तो किसी प्रकार से हरिजन नहीं हैं। इनके वर्ग में अगर 10 लाख आदमी जोड़ देते हैं तो 20 करोड़ आदमियों का उत्थान कैसे होता है? इसीलिये इंटेंशन का सवाल नहीं, डाइरेक्शन का सवाल है। एक नया क्लास आज बनता जा रहा। मुझे माफ करेंगे यदि मैं कहूं कि हरिजनों में से कोई मंत्री या एम०एल०ए०, आई०पी०एस० या क्लास I अफसर हो जाते हैं तो वे नीचे वाले हरिजनों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध नहीं करते हैं, खान-पान का रिश्ता छोड़ दिया जाता है इसलिये कि एक नया क्लास बनाने की जो परिपाटी है या रिजर्वेशन के जरिये होती है। मैं रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्लास करेक्टर बदलना चाहिये। कास्ट क्या है? मैं मानता हूं डा० राम मनोहर लोहिया ने जो कास्ट की परिभाषा दी है, सबसे अच्छी और वैज्ञानिक परिभाषा वही है। उन्होंने क्या परिभाषा दी—लिविंग क्लास क्लास है और जब क्लास मर जाती है तो वह जाति हो जाती है। जैसे कोई आदमी कामकार का काम करता है तो कामकार होता है, लेकिन जब वह कामकार काम को छोड़ कर एस०पी० हो जाता है तो वह जाति लिखता है, कुम्मार। हिन्दुस्तान में ब्राह्मण अपना काम छोड़ दे फिर भी बाबा जी बना हुआ है, क्षत्री का काम छोड़ दे तो क्लास बिकम्स कास्ट। स्वर्णकार का काम छोड़ दे, फि

[श्री कमल नाथ झा]

भी नाम सोनार लिखते हैं । सोनार या हेड क्लास, वही कास्ट है । इससे अधिक वैज्ञानिक परिभाषा जाति की कोई नहीं हो सकती । कास्टिज्म जो है वह मरणासन्न सामाजिक पद्धति है । जाति का नाम लेकर 25 वर्ष तक आदिवासियों के कल्याण की योजना बनाते रहे लेकिन—

"डिगहि न शंभु सरासनु जैसे"

हरिजन और आदिवासियों का कल्याण नहीं हो रहा है । मुट्ठी भर आदिवासियों के नाम पर, मुट्ठी भर लोगों का कल्याण भले हो जाय, लेकिन वह समाज वहां का वहां पड़ा रहेगा ।

इसलिये अगर आप हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण करना चाहते हैं तो इंटेंशन भले ही आपका ठीक हो, आपको अपना डाइरेक्शन बदलना होगा । डाइरेक्शन क्या बदलना होगा । आप को सोचना होगा कि वह लोग हैं कौन ? 99 परसेंट आदिवासी और हरिजन हैं एग्रीकल्चर लेबर । 70 से 60 परसेंट माइनारिटी कम्युनिटी के लोग, जिनको मुसलमान कहते हैं वह हैं एग्रीकल्चर लेबर और 50 परसेंट बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं एग्रीकल्चर लेबर और इनकी तादाद लगभग 20 करोड़ है इस देश में और इस बीस करोड़ एग्रीकल्चर लेबर टुगैदर विद दियर डिपेंडेंटस् के लिये मैं मिर्धा साहब से पूछना चाहता हूं कि इस 25 वर्ष में क्या एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद सैंटर में दिया गया ? एग्रीकल्चर हमारा कोर सेक्टर है और सब सुपरवाइजरी हैं । रियल एग्रीकल्चरिस्ट यही लोग हैं आज उन को दो रुपये रोज की मजदूरी मिलती है । इस महंगाई में और आप देखें कि इंडस्ट्रियल लेबर के लिये क्या सुविधा है ? बोनस उनके लिये, प्राविडेंड फंड उनके लिये, घाटे में भी उन को बोनस मिलना चाहिये, इसके लिये बोनस की परिभाषा भी बदलनी पड़ी और एम्प्लाइज स्टेट इंशोरेंस उन के लिये, ग्रेच्युटी उनके लिये और मैंने बार-बार कहा है कि आप एग्रीकल्चर लेबर को इस 25 वर्ष में कुछ नहीं दे सके । वह कैसे उठ पायेगा । मैंने प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में भी कहा था कि इसके लिये आप अपने डाइरेक्शन को बदलिये । यह स्टीरियो टाइप, आउट मोडेड, कास्ट एप्रोच, कम्युनल एप्रोच आज के समाजवादी समाज में नहीं चल सकता । आप एक कानून बनाइये और एक स्टेट को लेकर एक्सपेरीमेंट कीजिये साइड बाई साइड । मेरा प्रपोजल है कि हर एग्रीकल्चर लेबर को आप खैरात जैसी जमीन देते हैं । बिहार सरकार की जमीन दे दी जाय, वैस्ट लैंड दे दी जाय । वह भीख थोड़े ही मांगता है, उस को एक गांव में कम से कम वन फोर्थ आफ एन एकड़ वैस्ट जमीन दी जाए और दो हजार रुपया दिया जाए जिस से कि वह हरियाणा या गुजराती नस्ल की गाय खरीद सके या वह खरीद कर दे दी जाय और वह उस जमीन पर क्विक ग्रोइंग ग्रास लगाये, एलीफेंटा टाइप ग्रास, जिससे उसको दस, बारह सेर दूध रोज मिला करेगा और उस की आमदनी बनी रहेगी । आप वैस्टर्न इकोनामी की कापी करते हैं । क्या आप 40 हजार रुपया पर कैपिटा इंवेस्टमेंट कर सकते हैं ? वैसा कर के ही कोई 500 रुपये महीने की इन्कम कर सकता है । इंडियन इकोनामी में एग्रीकल्चर के साथ एनीमल हस्बेंडरी जोड़ दी जाये, तो 2,000 रुपये के इंवेस्टमेंट में एक फैमिली को 500 रुपये मासिक की इन्कम करायी जा सकती है । आप इंडियन इकोनामी सूटेड टू इंडियन कंडीशन्स जो हो उसे इवाल्व कीजिये । यह तो आप आंख मूद कर कापी कर रहे हैं । आप अपने कंट्री को न तो रूस बना सकते हैं और न अमरीका । अमरीका 50 परसेंट वर्ल्ड इकोनामी का कंट्रोल करता है । तो इंडिया न अमरीका हो सकता है और न रूस । इस लिये आप को अपनी इकोनामी इवाल्व करनी होगी । इसमें आपको दो हजार रुपया इंवस्ट करके दूसरे दिन भी वेट नहीं करना पड़ेगा । और आप उस फैमिली को 450 रुपये मासिक की आमदनी करा सकते हैं और जिस हरिजन को 450 रुपये महीने की आमदनी होगी वह अपने बेटे को पढ़ा लेगा, वह अपना घर भी बना लेगा और अगर उस पर कोई मुकदमा करेगा तो वह उस मुकदमे को भी लड़ लेगा । यह सारे जो सुपरफीशियल मैजर्स हैं कि उन को वकीलों की सहायता दी जाये या खैराती जमीन गांव की दे दी जाये, यह सारे के सारे ऐंटी सोशल

मैजर्स हैं । मेरी समझ में राहत का काम, खैरात का काम बहुत दिनों से चल रहा है देश में और समाजवाद में और खैरात में कोई रिश्ता नहीं है। इसलिये मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि और मैंने अपने चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से भी कहा था इस बातको । आप इसको करें ।

सैकिण्ड चीज यह कि जैसे गांव में आपने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनें बनाईं और छः-छः महीने में मजदूरों को काम मिला, उसी तरह से आप हरेक गांव में खेती मजदूरों की एक रिकोगनाइज्ड यूनियन बनायें और उसके लिये आप कुछ रुपया रख दीजियें मीन मंथ्स,मैं जब उनको एम्प्लायमेंट नहीं मिलेगी तो उसके लिये सर्टेन टाइप आफ वर्क इयर मार्क करके रखें, Employment facilities backed by additional source of income.

अगर ये दोनों चीज आप हरिजनों के लिये करना चाहते हैं तो आप को अपना डाइरेक्शन बदलना होगा । यह भीख मांगने की बात नहीं है ।

दिल्ली में 50 तल्ले का मकान बनाने की क्या जरूरत है । आखिर वे भी देश के नागरिक हैं उसके पास काम का हिस्सा है । वह कोई भिखमंगा नहीं है । वह मेहनत करता है । कैसी कंडीशन में काम करता है वह आप जानते हैं । चिलचिलाती धुप में काम करता है । हड्डियों को तपा देने वाले जाड़े में काम करता है । इंडस्ट्री लेबर एंड वर्किंग कंडीशन में मुकाबला करके देखें । आप उसको एम्प्लायमेंट नहीं दे सके । उसको एक कपड़ा मोटा नहीं दे सकते, तब आपको क्या मोरल और लीगल स्ट्रैंग्थ है कि आप 50 तल्ले का मकान बनायें ।

कास्टीज्म, कम्युनलिज्म की अब ऐसी बीमारी चल पड़ी है कि पहले तो हरिजन कहता था कि कि हम ब्राह्मण हो जायेंगे । बैकवर्ड भी कहता था कि हम क्षत्रीय हो जायेंगे । जब से यह कास्ट एप्रोच हुआ बैकवर्ड भी कहता है कि हमें ऐसा ही रहने दो । बैकवर्ड परमानेन्ट बैकवर्ड रहना चाहता है, फार्वर्ड नहीं बनना चाहता है । कितनी सिपेथी इनको हरिजनों के साथ हो सकती है, यह यहां के खाली बैंच बता रहे हैं। What is his ? इंटेन्शन और उद्योग ?

"उद्योगे ही सिद्धयन्ति कार्याणी न मनोरथे"

केवल मनोरथ करने से, केवल इंटेन्शन से कुछ नहीं होता । राम ने भी कहा था कि भावना से कर्त्तव्य ऊंचा है । इसलिये आपको ऐसी लाइन पकड़नी चाहिये, जिससे खेतों में काम करने वाले जो खेतिहर मजदूर हैं और मैं हरिजन नेता से भी कहूंगा कि अपनी सीट रिजर्व कराने के लिये, कुछ करें । गांधी जी ने हरिजन का नाम सोशल कान्शयस लिया था, वह जरूरी था । Every Harijan is now conscious; every Adivasi is now conscious. अब चाहिये उसकी आवश्यकता की पूर्ति और आवश्यकता की पूर्ति तभी होगी जबकि आप का इकोनोमिक एप्रोच होगा, जब आपका सोशल एप्रोच होगा, जब आपका साइंटिफिक एप्रोच होगा।

मैं आपका बहुत समय नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता था कि प्लानिंग कमीशन और होम मिनिस्टरी बैठ कर एक नया डाइरेक्शन दे । जैसा हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमको एक नया डाइरेक्शन दिया उसको एक्शन में ट्रांसलेट करने का । 'गरीबी मिटाओ' एक नई दिशा है । यह तो मिटेगी । आप मिटायें या न मिटायें । जैसे कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन तुम उनको मारो या न मारो ये तो मरेंगे । सवाल यह है कि इतिहास में इसको मार कर जश का भागी बनना । इसी तरह से इस देश से गरीबी मिटाना है । चाहे आप मिटायें या न मिटायें, हम मिटायेंगे । प्रश्न यह है कि आप भी आज के इतिहास में यश के भागी बनें । जैसे कि नेहरू जी, गांधी जी और पटेल

[श्री कमल नाथ झा]

जी तथा दूसरे लोग देश को आजाद करा कर जश के भागी बने । उसी तरह से आप भी नया डाइरेक्शन देकर गरीबी मिटा कर जश या अपयश जो भी आप बनना चाहते हैं, बनें। मैं अपील करता हूं कि आपके माध्यम से कि आप और हम जश के भागी बनें ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now the discussion on this subject is closed and tomorrow the Minister will reply.

The House then adjourned at forty-five minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 21st November, 1973

Scheduled Tribes

MGIPRRND-38 RSS/73—Sec. H (N.S.)-3l-l-74~595.